मासिक समाचार पत्र

लोकविद्या पंचायत

● सूचना युग में बराबरी के विचार के पुनर्निर्माण का पत्र ●
● लोकविद्याधर समाज के पुनर्संगठन का वैचारिक आधार पत्र ●
● पूँजी आधारित समाज के स्थान पर ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का विचार पत्र ●

प्रकाशन का स्थान : विद्या आश्रम, सा 10/82 ए, अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007

वर्ष 1, अंक 12, कुल पृष्ठ : 8 | अप्रैल 2012 | सहयोग राशि : 5 रुपये

बिहार में लोकविद्या जन आंदोलन समागम

विजय कुमार

दरभंगा में हुए लोकविद्या जन आन्दोलन समागम की आयोजन समिति

बिहार के दरभंगा में 31मार्च-1अप्रैल को दो दिवसीय लोकविद्या जन आन्दोलन का समागम आयोजित हुआ। समागम आयोजन हेतु श्री चन्द्रवीर नारायण के संयोजकत्व में 21 सदस्यीय आयोजन समिति गठित कर समागम हेतु तैयारी शुरू की गई। समागम करने का उद्देश्य था कि लोकविद्या जन आंदोलन के वाराणसी सम्मेलन के 12 सूत्री कार्यक्रम की समझ बढ़ाना, लोकविद्या विचार को विहार में फैलाना, लोकविद्या समाज को एकता के सूत्र में बांधना और स्थानीय मुद्दों की पहचान कर संगठन को विस्तार देने एवं संघर्ष के लिए जमीन तैयार करना। आयोजन समिति में जे. पी. आंदोलन से निकले कार्यकर्ता, समाजवादी, साम्यवादी पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता, गांधीवादी, सामाजिक कार्यकर्ता, कारीगर, कलाकार, किसान, महिला, पत्रकार और बुद्धिजीवी प्रमुख थे।

समागम का उद्घाटन प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री मानस बिहारी वर्मा एवं अध्यक्षता जिला परिषद दरभंगा के अध्यक्ष श्री हरि साहनी ने किया। समागम में बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री मिश्रीलाल यादव सहित 25 साथियों ने विचार रखे। मिथिलांचल के आठ जिलों से लगभग 150 से 200 लोगों की भागीदरी के साथ तथा वाराणसी, लखनउ, इन्दौर व सिंगरौली से आये लोकविद्या जन आन्दोलन के साथियों की उपस्थिति में हुई चर्चा में मुख्य रूप से उभर कर आया कि लोकविद्याधर समाज साजिश के तहत गरीब, पीड़ित, विस्थापित और सरकारी उदासीनता का शिकार है, ऐसी स्थिति में लोकविद्याधर समाज की एकता एवं संघर्ष से ही मुक्ति मिलना संभव है। समागम में मुख्य रूप से चर्चा उभर कर आई कि मिथिलांचल में नदियों का जाल है। लोकविद्याधर समाज नदियों के साथ जीने की कला से वाकिफ रहने के कारण नदियों के पानी का सदुपयोग करके अपनी जीविका अक्षुण्ण रूप से चला रहे थे। पानी में ही अपनी खुशहाली देखते थे लेकिन जब से तकनीकीविद् एवं सरकार की नजरें नदियों पर पड़ी और नदियों को कैद करने लगी तब से इस इलाके की बर्बादी की कहानी आम हो गयी। इसलिए समागम में यह दावा पेश किया गया कि बाढ़, सूखा और जल-जमाव जैसी समस्याओं का समाधान लोक विद्याधर समाज के पास ही है। नदी को मुक्त छोड़ दिया जाए हम इसके साथ जी लेंगे। कोसी, कमलावलान, अधवरा समूह और वागमती नदी को सरकार द्वारा कैद करने के कार्यक्रम की आलोचना की गयी। सम्मेलन में यह भी मांग उठी कि सरकार अपनी परियोजना रोके अन्यथा लोकविद्याधर समाज बाध्य होकर सरकार की योजना का विरोध करेगी।

समागम में परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी—लोकविद्या के आधार पर पूरे तर्क के साथ उठाई गयी और इसलिए संघर्ष हेतु कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ने की बात की गई।

समागम में लोकविद्या के वैचारिक पक्षों को मजबूत करने के लिए एक स्मारिका प्रकाशित कर बांटा गया। लोकविद्या की समझ स्पष्ट करने हेतु स्थानीय लोगों के बीच पर्चा बांटा गया और पोस्टर के माध्यम से आंदोलन के मुद्दों का प्रसार किया गया।

समागम समाप्ति के बाद सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक में समागम के उत्साह और आवाज को देखते हुए यह विचार किया गया कि पहले संगठन को मजबूत किया जाए। इसके लिए सदस्यता अभियान चलाया जायेगा। क्षेत्र में एक लोकविद्या आश्रम का निर्माण किया जायेगा। यह आश्रम जन आंदोलन के केन्द्र के रूप में उभरेगा और एक समाचार बुलेटिन का प्रकाशन भी शुरू किया जायेगा।

स्थानीय बुद्धिजीवी एवं पत्रकारों के लिए लोकविद्या यह एकदम नया विचार था, उनकी तरहफ से कई सवाल आये जवाब से संतुष्ट होकर उनकी सक्रिय भागीदारी रही और सभी अखबारों ने दोनों दिन का खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया।

समागम में आये अतिथियों को रहने एवं खाने इत्यादि की व्यवस्था आम लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया।

विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ 2 देखें।

●

परमाणु बिजली का व्यापक विरोध

कुन्डनकूलम, तमिलनाडु में सरकार परमाणु बिजली घर बनाने पर आमादा है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चारो ओर बस्तियां हैं और किसी दुर्घटना के वक्त बहुत जल्दी लाखों लोगों को वहां से हटाना आसान नहीं है। जापान में फुकुशिमा में मार्च 2011 में हुई परमाणु बिजली घर में विस्फोट की जगजाहिर दुर्घटना ने विरोध को बड़ा बल दिया है। देशभर में सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने इस परमाणु बिजली घर बनने के विरोध में प्रदर्शन किये हैं जो अभी भी जारी हैं। हाल में तमिलनाडु सरकार ने इस बिजली घर के बनने को हरी झंडी दिखा दी है। नतीजे स्वरूप बिजली घर बनाने वालों को बल मिल गया।

जब तक देश में बिजली के वितरण और इस्तेमाल की नीति नहीं तय हो जाती तब तक बिजली उत्पादन के सारे तर्क बेमानी हैं। बड़े-बड़े बिजली घर जगह-जगह बनाये गये हैं और सच्चाई यह है कि आसपास के तमाम गांव अंधेरे में ही रहते हैं। परमाणु बिजली घर का विरोध तो जायज है ही। परमाणु बिजली, परमाणु बम, परमाणु हथियार, युद्ध में इनका इस्तेमाल, संयत्रों के स्थान पर दुर्घटना का उस भौगोलिक क्षेत्र पर प्रभाव और सामान्य स्थितियों में भी इन कारखानों के आसपास में विकिरण का फैलाव

भोपाल में गैस पीड़ित समाज के बीच परमाणु बिजली घर का विरोध

और लोगों के स्वास्थ्य पर उसके गंभीर प्रभाव इन सब बातों को एक दूसरे से अलग करके विशेषज्ञता से भरे तर्क प्रस्तुत करना, लोगों को धोखा देने के बराबर है, उनसे असलियत छुपाकर उनकी जिन्दगी से खेलने के बराबर है।

●

लोकविद्या जन आंदोलन

मध्यप्रदेश का प्रान्तीय अधिवेशन

सिंगरौली, 9-10 अगस्त 2012

मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित सिंगरौली जिला जंगलों, पहाड़ों, नदियों और विजली उत्पादन का वह क्षेत्र है जो दिल्ली के नजरिये से विकास का नमूना है और किसानों व आदिवासियों की नजर में महा विनाश का क्षेत्र। एक तरफ है हजारों मेगावाट बनाने वाले विजली उत्पादन के कारखाने और दूसरी तरफ इनके चलते मुश्किल से अपनी जिविका चला रहे आदिवासियों और किसानों का भुखमरी में ढकेला जाना है। इन कारखानों के चलते पूरा इलाका कोयले की खदानों, पानी के फैलाव, राख के निस्तारण, वातावरण में धुआँ व तपन, ठेके के मजदूरों की बस्तियों, नौकरी करने वालों की कालोनियों और नये बाजारों से पट जाता है। दूसरी ओर किसान, आदिवासी, छोटे-छोटे दुकानदार, कारीगर सभी क्षेत्रीय निवासी अपनी ज़िन्दगी, उसके संसाधनों, घर द्वार, जमीन, पेशा, छोटे-मोटे धन्धों और अपने बाजार सभी से हाथ धो बैठते हैं। जंगल कट जाते हैं, पानी के बहाव अवरुद्ध हो जाते है, जमीन छीन ली जाती है, जमीन के नीचे का पानी गायब हो जाता है और पूरा क्षेत्र सामाजिक एवं पर्यावरणीय महा संकट से ग्रस्त हो जाता है। ये सब लोग और ये पूरा क्षेत्र लोकविद्या के मार्फत अपनी पहचान रखता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों से अपनी विद्या के बल पर अपनी जिन्दगी चला रहे होते हैं। विकास के नाम पर हो रहे इस हमले को लोकविद्या के नाम पर ही चुनौती दी जा सकती है। विश्वविद्यालय का ज्ञान इसे विकास कहता है और लोकविद्या की दृष्टि में यह विनाश है। जरूर है कि ये किसान और आदीवासी और उनके सहयोगी समाज अपने ज्ञान यानि लोकविद्या का एक आन्दोलन खड़ा करें। ऐसे ही आन्दोलन को लोकविद्या जन आन्दोलन कहा गया है।

सिंगरौली अधिवेशन में विभिन्न जिलों से किसान, आदिवासी, कारीगर, छोटे दूकानदार, महिलाएँ और सामाजिक कार्यकर्त्ता इकट्ठा होंगे और निम्नलिखित तीन मुद्दों पर चर्चा करके इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने की नीति बनायेंगे।

1. **लोकविद्या के आधार पर पक्की आय की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसे जो आता है उसके बल पर नौकरी दी जाय और हर परिवार में कम से कम एक नौकरी हो। इस नौकरी में वेतन सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर हो।**
2. **ये परियोजनाएं पूरे इलाके पर बहुआयामी विनाशकारी प्रभाव डालती हैं सारी बात को केवल प्रत्यक्ष विस्थापितों तक सीमित करना सरासर बेइमानी है। हर परियोजना के प्रस्ताव के साथ प्रभावित क्षेत्र के सुनियोजित पुनर्संगठन का प्रावधान भी होना चाहिए। इसके लिए परियोजना के हिस्से के रूप में निश्चित रकम आवंटित होनी चाहिए जिसके खर्च का अधिकार लोक पंचायतों के पास होना चाहिए।**
3. **विजली वितरण की नीति बनाये बगैर विजली उत्पादन की जरूरत बताना जनता के साथ धोखा करना है। बड़े-बड़े विजली घरों के बगल के गाँव अंधेरे में रहने मजबूर होते हैं। पहले यह तय होना जरूरी है कि किसानों और कारीगरों को उनके जरूरत की पूरी विजली मिलेगी और यह की हर ग्रामीण घर को शाम 6 से 10 बजे तक विजली मिलेगी। वास्तव में गाँवों को महानगरों के बराबर की विजली मिलनी चाहिए तभी विजली उत्पादन की परियोजनाओं को किसान और आदिवासी समुदाय के लोग समर्थन दे सकते हैं।**

सम्पर्क : अवधेश कुमार
सृजन लोकहित समिति
ढोटी, बैढ़न
मो.नं. : 09425013524

लोकविद्या जन आंदोलन–बिहार प्रांतीय समागम

31 मार्च - 1 अप्रैल 2012, दरभंगा

रविशेखर

बिहार में लोकविद्या जनांदोलन का प्रथम दो दिवसीय प्रांतीय समागम 31 मार्च - 1 अप्रैल 2012 को दरभंगा जिले में आयोजित हुआ, इस समागम में भाग लेने के लिए आसपास के कई जिलों से तथा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में उत्साहित साथी उपस्थित थे। समागम के दौरान प्रतिभागियों में दिखे उत्साह से भविष्य में मिथिला क्षेत्र में लोकविद्या जनांदोलन के प्रचार-प्रसार की प्रचुर सम्भावनाएं स्पष्ट दिख रही थीं। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में जल प्रबंधन के नाम पर चलायी जा रही योजनाओं के खिलाफ स्थानीय लोकविद्याधर समाज में एकजुटता का जो भाव दिख रहा था उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि मिथिला क्षेत्र इस जनांदोलन में अपनी महती भूमिका निभाएगा। इस दो दिवसीय समागम में आये हुए अधिकांश साथी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, जिनमें किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, कारीगर, कलाकार, पत्रकार और बुद्धिजीवी आदि प्रमुख थे।

इस समागम के चारों सत्रों में लोकविद्याधर साथियों और अन्य की करीब 150 से 200 की संख्या में भागीदारी हुई। बिहार के मधुबनी, वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, सुपौल आदि जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के इंदौर व सिंगरौली जिले से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी व लखनऊ और दिल्ली से प्रतिभागियों ने समागम में हिस्सा लिया। प्रथम सत्र में मंच पर मौजूद दरभंगा जिले के निवासी और सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. मानस बिहारी वर्मा, विद्या आश्रम वाराणसी से आये सुनील सहस्त्रबुद्धे और लोकविद्या जनांदोलन के राष्ट्रीय संयोजिका डॉ. चित्रा सहस्त्रबुद्धे, दरभंगा जिले के जिला परिषद अध्यक्ष हरी साहनी, बिहार के प्रांतीय संयोजक श्री विजय कुमार, समागम की तैयारी समिति के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

चर्चा में प्रतिभागियों ने प्रमुख रूप से लोकविद्याधर समाज की एकता में ही इस समाज की प्रतिष्ठा और शक्ति निहित होने पर बात की तथा—जिस प्रकार एक साजिश के तहत यह समाज गरीबी, उत्पीड़न, विस्थापन और सरकारी उदासीनता का शिकार है, ऐसे में इसकी एकता में ही इस समाज के उद्धार का आधार बनता है—पर बातचीत काफी सघनता के साथ हुई। मिथिला क्षेत्र में स्थाई तौर पर बन चुके सूखे और बाढ़ के संकट ने पूरे दिन की चर्चा में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बनाए रखा और स्थानीय लोकविद्याधर समाज की तरफ से लगातार वे तर्क और उपाय रखे गये जिनके आधार पर अगर काम हो तो स्थानीय जल प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से जो विसंगतियां पैदा हुई हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है।

जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई वे थे—लोकविद्या जनांदोलन का सांगठनिक प्रसार, नदी जल प्रबंधन में मिथिलांचल की पारंपरिक व्यवस्थाएं और पारंपरिक कला और कारीगरी आदि पर बड़ी पूंजी के बढ़ते संकट, प्रतिभागियों के द्वारा पूरी चर्चा की संरचना इन मुद्दों के माध्यम से व्यवस्थित की गयी—लोकविद्या के बल पर सबको नौकरी, पूंजी के हस्तक्षेप से अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने व्यवसाय से लोकविद्याधर समाज का विस्थापन, नदियों-तालाबों को सरकार द्वारा बेतरतीब बांधा जाना और खेती किसानी से लेकर आम जनजीवन पर पड़ते दुष्प्रभाव, विश्वविद्यालयीय शिक्षा के माध्यम से समाज में बढ़ते विभेद, लोकविद्या जनांदोलन को अनपढ़ लोगों के ज्ञान आंदोलन के रूप में देखना और लोकविद्या ताना-बाना की संभावित संरचना एवं स्वरूप, ताना-बाना का स्वरूप क्या हो, इस पर पहले से विभिन्न आयामों और जगहों पर चल रही चर्चा को मिथिलांचल के क्षेत्र में और ज्यादा खोलने की कोशिश हुई, ताकि इसके संभावित स्वरूप के बतौर कुछ और प्रस्ताव आ सकें।

वाराणसी अधिवेशन में प्रस्तावित बारह मांगें इस समागम की स्मारिका में प्रकाशित थे। उन पर लगभग 25 वक्ताओं ने अपने विचार साझा किये तथा सहमति व्यक्त की। समागम के सभी सत्रों में पारंपरिक जल प्रबंधन के ज्ञानियों की प्रतिभागिता ज्यादा रही, जो इस दावे को और मजबूती के साथ पेश करता है कि मिथिलांचल की सबसे बड़ी समस्या के समाधान के रूप में लोकविद्या जनांदोलन आम जनता के हित में वैसे लोगों का आंदोलन है जो वर्तमान व्यवस्था में अनपढ़ कहे जाते हैं, तथा यह जनांदोलन देश-काल-परिस्थिति, तीनों के लिहाज से न केवल प्रासंगिक है बल्कि अवश्यम्भावी भी है।

लोकविद्या जनांदोलन की व्यावहारिकता पर समीक्षात्मक चर्चा में यह निकल कर आया कि लोकविद्या की प्रतिष्ठा 21वीं सदी में गांधी की विचारधारा का अगला स्वरूप है। आज की प्रचलित ज्ञान धाराओं के बारे में चर्चा के दौरान यह बात समझ में आयी कि इसमें अनपढ़, मूर्ख और अज्ञानी को पर्यायवाची बना दिया गया है। जबकि ये प्रचलित ज्ञान धाराएं मूलतः विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया लोकविद्या का संगठित स्वरूप ही हैं। इसीलिए, विश्वविद्यालयों का हिमायती वर्ग लोकविद्या की पुनर्प्रतिष्ठा का विरोधी है। लोकविद्या के नवीनीकरण के बाबत यह दावा कि लोकविद्या समाज के साथ प्रासंगिक रिश्ते को बनाये हुए परिष्कृत होती है और इसके लिए स्कूल कॉलेज आदि की जरूरत नहीं पड़ती। बनारस में हुए अधिवेशन की निरंतरता में पुनः पेश हुआ। लोकविद्या को नजरअंदाज किये जाने और इसकी उपयोगिता को साजिशन कम करके आंके जाने की कोशिशों के खिलाफ लोकविद्याधर समाज के प्रत्येक एकल परिवार के एक सदस्य को लोकविद्या के बल पर एक पक्की नौकरी की मांग दरभंगा में हुए इस प्रथम प्रांतीय अधिवेशन में पूरे जोश और तर्क के साथ पुनः उठायी गयी। इस संदर्भ में इंदौर में युवाओं के एक बड़े समूह से हुई एक अनौपचारिक वार्ता के हवाले से यह बात भी समझ में आई कि सबको नौकरी की मांग जहां एक ओर लोकविद्याधर समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करती है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह मांग युवाओं की एक बड़ी जमात, जो विश्वविद्यालयीय संस्कृति के उपज हैं, में रोष भी पैदा करती है। ऐसे में सबको नौकरी के सवाल पर वृहत पैमाने पर चर्चा छेड़े जाने की आवश्यकता है ताकि इस मांग को लोकविद्या जनांदोलन की एक प्रमुख आधार-मांग के रूप में प्रस्तावित और प्रसारित किया जा सके। समागम के अंतिम सत्र में तीन सूत्री प्रस्ताव स्वीकृत किया गया—

1. **घोषित मुद्दों पर सहमति के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों को चिन्हित कर बिहार प्रांत में लोकविद्या जनांदोलन का विस्तार किया जाये।**
2. **बाढ़ और सूखे का हल लोकविद्या के पास ही है और इसके समाधान के लिए लोकविद्याधर समाज संगठित होकर इसके निदान का दावा पेश करे।**
3. **देश में लोकविद्या समर्थक लोग और लोकविद्याधर समाज, जैसे किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटे दुकानदार, महिलाएं, कलाकार, चिन्तक, दार्शनिक आदि के बीच सम्बन्ध और संपर्क बढ़ाने के लिए लोकविद्या ताना-बाना को सशक्त किया जाये।**

अलग-अलग सत्रों में सर्वश्री दिलीप कुमार 'दिली', देवनाथ देवन, मिसरी लाल यादव (बिहार विधान परिषद सदस्य), अवधेश द्विवेदी, लक्ष्मण प्रसाद, संजीव कीर्तने, विजय कुमार, चंद्रवीर नारायण, रवि शेखर, सौम्या झा, सुनील कुमार मंडल आदि ने अध्यक्षता की। इस प्रांतीय समागम के लिए गठित आयोजन समिति में सर्वश्री विजय कुमार (मधुबनी), अजय कुमार (वैशाली), चंद्रवीर नारायण और मधुसूदन महतो (दोनों दरभंगा), रमेश पंकज (मुजफ्फरपुर), सुनील कुमार मंडल और राजदेव रमण (दोनों मधुबनी), शिवाजी महतो और रामचंद्र महतो (दोनों समस्तीपुर), डॉ. रविन्द्र पाठक और डॉ. प्रमिला पाठक (दोनों गया) शामिल थे। तैयारी समूह में हृदय नारायण चौधरी (दरभंगा), रामचरित्र पंडित (सुपौल), मो. सयाल हाशमी, रघुवीर नारायण, श्रीमती आशा चौधरी, श्रीमती उमा भारती, रामप्रवेश पासवान (सभी दरभंगा) आदि शामिल रहे।

●

तटबंध बनाना बंद करो

पूरा मिथिला क्षेत्र तटबंधों की राजनीति से ग्रस्त है। लालू यादव जी को बात कुछ समझ में आयी थी और उनके शासनकाल में नदियों पर तटबंध नहीं बनाये गये। जब से नितीश जी मुख्यमंत्री हुए हैं फिर से तटबंध बनने शुरू हो गये हैं। हिमालय से सीधे अवतरित हो रही मिथिला की सारी नदियां इतनी मिट्टी साथ लेकर आती हैं कि इनको बांधना पूरे इलाके का भूगोल ही नष्ट कर देता है। सरकार कहती है कि तटबंध बनाकर वह गांवों को डूबने से बचाती है और लोग कहते हैं कि तटबंध बनाने में गांवों को डुबोने का पक्का इंतजाम है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी चले जाइये पानी को बांधने से होने वाली बरबादी साफ नजर आती है। लोकविद्या के मिथिला समागम के तुरंत बाद विद्या आश्रम के साथियों ने दरभंगा से समस्तीपुर की ओर बढ़कर तेरह नदियों के इस इलाके का दौरा किया जहां तटबंधों का जाल बिछाया जा रहा है। बिहार लोकविद्या जन आंदोलन के साथी **चन्द्रवीर नारायण** साथ में थे, उन्होंने विस्तार से स्थिति को समझाया और जमीन पर नक्शा बनाकर समझाया कि किस तरह से ये तटबंध पूरे इलाके के लिए विनाशकारी साबित होंगे। स्थानीय गांवों के लोगों से और महिलाओं से बातचीत हुई। वे इन नदियों के पानी की व्यवस्थाओं को बखूबी समझते हैं लेकिन शासन-प्रशासन की सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं और उन्हें लागू करने की दबंगई के आगे अपने को विवश पाते हैं। मिथिला क्षेत्र के लोकविद्या जन आंदोलन की एक प्रमुख मांग यह है कि तटबंध बनाना बंद होना चाहिए। बाढ़-सूखे और नदियों के सबसे अच्छे इस्तेमाल की पक्की समझ लोकविद्या में है, उन लोगों के ज्ञान में है जो उन क्षेत्रों के निवासी हैं। बिहार सरकार का तटबंधों को बनाना तुरंत बंद कर देना चाहिए और थोड़ा लोगों का भी सुनना चाहिए।

अब लोकविद्या के आधार पर खड़े होने वाले आंदोलन वह जागृति लायेंगे जो बागडोर अपने हाथ में लिये बगैर नहीं मानेंगी।

सबको रोजगार दिलवाने और पंजाब, मुम्बई और सूरत की ओर पलायन रोकने का रास्ता भी ये ही बनायेगी।

●

विस्थापन के सवाल पर ज्ञान पंचायत काली बिल्लोद, इन्दौर

मोहनसिंह सोलंकी

विस्थापन रोको बाजार मोड़ो अभियान के तहत लोकविद्या समन्वय समिति ने ग्राम काली बिल्लौद जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश में एक ज्ञान पंचायत का आयोजन दिनांक 25 मार्च रविवार 2012 के दिन संपन्न किया। इन्दौर धार जिले के लगभग बीस गांवों के किसानों, आदिवासियों, कारीगरों और छोटे दुकानदारों ने ज्ञान पंचायत में भागीदारी निभाई और अपने अंचल की विकास की अवधारणा पर बातचीत की है।

भारी पैमाने पर फैलते उद्योगों ने जमीनें हड़पकर यहां के लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर किया है। सरकारें (केन्द्र और राज्य) उद्योगों की तरफदारी करती हैं और अंचल के विकास की झूठी तस्वीर पेश करती हैं। अंचल के निवासियों को न तो उद्योगों में पक्की नौकरी मिलती है और न ही वे स्वयं की जमीनें, खेती और अन्य व्यवसाय बचा पाते हैं।

ज्ञान पंचायत में ग्राम माधोपुर के श्री विष्णू जिराती ने ऑटो टेस्टिंग ट्रेक बनने से उजड़ गये ग्रामवासियों की व्यथा सुनाई। ग्राम अकोलिया के श्री मोहन पटेल, ग्राम चैनपुरा के श्री कल्याण सिंह, ग्राम चायड़ीपुरा के श्री जगराम पटेल, ग्राम सुलावड़ के श्री हिन्दू सिंह, ग्राम सागौर के श्री मदनसिंह, ग्राम रणमल बिल्लौद के श्री भेरूसिंह सोलंकी ने अपने अपने गावों की बातें रखी। ग्राम काली बिल्लौद के श्री बाबूसिंह पटेल ने न्यू पीथमपुर बेटमा इण्डस्ट्रियल क्लस्टर बनाने का विरोध किया। एक वर्ष से यहां के नौ गांवों के लोगों द्वारा किये जा रहे संघर्ष की चर्चा की। श्री नरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री मोहनसिंह सोलंकी, श्री गणेश परमार ने इस संघर्ष को नई दिशा देने पर जोर दिया। कूटी-सागौर के श्री भूरूभाई ने कहा कि ऐसी ज्ञान पंचायतें प्रतिमाह अलग-अलग गांवों में करनी होगी ताकि इस क्षेत्र के लोकविद्याधारियों को एकजुट किया जा सके। श्री भंवर सिंह पटेल, श्री राधेश्याम सोलंकी, श्री तपन भट्टाचार्य, श्री इन्द्र विक्रमसिंह, श्री डॉ. राजेन्द्र शर्मा, श्री दाजी ने भी अपने विचार रखे। श्री अनिल त्रिवेदी ने पूरे अंचल के वर्तमान विकास पर कई सवालिया निशान खड़े किये और इसे विकास नहीं कहते यह तो लोकविद्याधरों के विनाश का रास्ता है, इस बात को रखा। मालवी भाषा में बोलते हुए उन्होंने अगली रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर बात की। सभी ने ऐसी ज्ञान पंचायतें आयोजित करने की जरूरत को स्वीकार किया और सहयोग का वचन दिया।

इस ज्ञान पंचायत में बनारस सारनाथ से पधारे विद्या आश्रम के श्री सुनील सहस्त्रबुद्धे और श्रीमती चित्रा सहस्त्रबुद्धे ने लोकविद्याधर समाज ही क्यों विस्थापित होता है इस बात पर लोकविद्या दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत पर जोर दिया। देशभर में किसान, कारीगर, आदिवासी और छोटे-छोटे दुकानदार ही क्यों खदेड़े जा रहे हैं इसको समझना होगा। इन सभी की विद्या यानि लोकविद्या का टकराव, संगठित विद्या यानि विश्वविद्यालयीय विद्या से हो रहा है। धर्म और पूंजी पर आधारित राजनैतिक व्यवस्थाओं में ऐसे ही विकास को राजनैतिक मुद्दा बनाया है जिसमें बड़े पैमाने पर लोकविद्याधारी विस्थापित होंगे। श्रीमती चित्रा सहस्त्रबुद्धे ने लोकविद्या जन आंदोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रखते हुए बताया कि यह जनआंदोलन लोकविद्याधारियों का ज्ञान आंदोलन है और इस आंदोलन से लोकविद्याधर समाज की स्थापित एकता होगी और इसी एकता में विस्थापन का जवाब है। ज्ञान पंचायत में कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये।

1. **लोकविद्या समन्वय समिति का विस्तार किया जायेगा और उसमें गांवों के बुजुर्ग और युवाओं को शामिल किया जायेगा।**
2. **प्रत्येक गांव के भूमि अधिग्रहण अथवा अन्य विस्थापन से संबंधित जानकारियों के दस्तावेजों को एकत्रित किया जायेगा।**
3. **वर्तमान विकास की अवधारणा का नक्शा प्रत्येक गांव में बनाए और साथ ही साथ लोकविद्या के आधार पर विकास की अवधारणा को भी नक्शे के साथ में बनाया जाये।**
4. **लोकविद्या जनआंदोलन के मुद्दों पर सहमति जताते हुए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा।**
5. **पूरे अंचल के लोकविद्याधारियों की एकता स्थापित करने के लिए विभिन्न तरीके खोजने होंगे। जैसे लोकविद्या कला यात्रा का आयोजन, लोकविद्या ताना बाना के कार्यक्रम।**
6. **प्रतिमाह एक गांव में एक वृहद लोकविद्या ज्ञान पंचायत का आयोजन किया जायेगा।**

माह मई में ग्राम सुलावड़ में लोकविद्या ज्ञान पंचायत का आयोजन करने पर सहमति हुई है।

ग्रामीण महिला को पक्की आमदनी का काम मिले

श्रीमती भँवर चौहान

इन्दौर के दक्षिण में बसे गांव उमरीखेड़ा में ग्रामीण महिलाओं के बीच 26 मार्च 2012 को 'लोकविद्या जन आंदोलन में महिलाओं की भूमिका' विषय पर बैठक हुई। श्रीमती मंगला हार्डिया और श्रीमती भँवर चौहान ने इस बैठक को संयोजित किया था। बैठक में यह उभरकर आया कि ग्रामीण महिलाओं के सामने रोजगार की विकट समस्या है। किसानी और कारीगरी के टूट जाने से उनके पुरुषों की आमदनी टूट ही गयी है साथ ही छोटी दुकानदारी या मजदूरी करके गुजर-बसर करने लायक आमदनी नहीं हो पाती। स्त्रियां पहले जो काम कर लिया करती थीं वे भी सब बन्द हो चुके हैं। गांव के विकास के नाम पर तमाम सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं लेकिन वे गुजर-बसर के लायक कोई व्यवस्था नहीं दे पाती हैं।

लोकविद्या जन आंदोलन की ओर से वाराणसी से आई चित्रा सहस्त्रबुद्धे ने इस बात को रखा कि विकास के लिए आ रहे तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता यह बताने के लिए आपके गांव आते हैं कि आपमें क्या कमी है—आप अशिक्षित हैं, आप गंदगी में रहते हैं, आपको सलीके (आधुनिक ढंग) से काम करना नहीं आता, आप बीमार का इलाज नहीं कराते, आप देश-दुनिया के बारे में नहीं जानते, आप अंधविश्वासी हैं वगैरह। उनकी यह सोच हमारे खिलाफ एक साजिश की तरह काम करती है। बात एकदम उल्टी है। गांव की हर स्त्री के पास तरह-तरह की विद्यायें हैं। यह विद्या या ज्ञान ही स्त्रियों की शक्ति है, इसे पहचानना होगा।

खेती का, बीज का, कारीगरी का, भोजन के विविध व्यंजन बनाने का, भण्डारण का, सिलाई-कढ़ाई-बुनाई का, स्वास्थ्य की देखभाल का, पशुओं और पेड़-पौधे की देखभाल का, विभिन्न कारीगरी का, दुकानदारी का आदि सभी का ज्ञान ग्रामीण स्त्रियों के पास है। लोकविद्या जन आंदोलन इस ज्ञान को लोकविद्या कहता है और लोकविद्या किसी भी तरह से स्कूल-कॉलेज के ज्ञान से कम दर्जे का ज्ञान नहीं है। आंदोलन की यह प्रमुख मांग है कि लोकविद्या के बल पर यानि जिसे जो आता है उसके बल पर हर वयस्क (स्त्री और पुरुष) को पक्की नौकरी मिले। बैठक में इस विचार पर बहुत-सी महिलाओं ने अपनी राय रखीं। यह भी कहा कि हम तो दिनभर खटते हैं लेकिन आमदनी का कोई भरोसा नहीं होता जबकि सरकारी कार्यालयों में जब जाओ तब कर्मचारी गायब रहते हैं पर उनको हर महीने पक्की तनख्वाह मिलती है। कितना अच्छा हो अगर हम अपनी चाय की दुकान चलायें—चाहे कितना ही खटना हो, मगर पक्की तनख्वाह होगी तो हमारे बच्चों के चेहरे भी खिले हुए दिखेंगे। बैठक के अंत में दो बातों पर सहमति हुई :

1. कोई भी बाहरी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, विकास के कार्यकर्ता या नेता, गांव में आयें और उनके मुंह से गांव वालों या स्त्रियों को अज्ञानी या अशिक्षित कहा जाये तो महिलाएं तुरंत अपना विरोध जाहिर कर खुद को और गांव वालों को लोकविद्या का ज्ञानी कहें। खुद को अज्ञानी पुकारे जाने का विरोध करें।
2. लोकविद्या के बल पर पक्की नौकरी की मांग को सामने रखें। स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का आधार सरकारी कर्मचारी के बराबर पक्का वेतन मिलने में ही है। लोकविद्या जन आंदोलन के मुद्दों पर सहमति जताते हुए महिलाओं ने गांव में इन पर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया।

ग्राम पालडि में लोकविद्या युवा शिविर

सुमेर सिंह राठौर

विस्थापन रोको बाजार मोड़ो अभियान के तहत लोकविद्या समन्वय समिति ने ग्राम पालड़ी तहसील देपालपुर जिला इन्दौर में दिनांक 26 मार्च 2012 को एक लोकविद्या युवा शिविर का आयोजन किया।

लोकविद्या के आधार पर एक पक्की नौकरी मिले जिसका वेतन सरकारी कर्मचारी के बराबर हो इस मुद्दे पर युवाओं ने बहस में अपनी भागीदारी की है।

आसपास के गांवों से आये युवाओं ने लोकविद्या के आधार पर पक्की नौकरी मिलनी चाहिए इस बात पर तुरन्त अपनी सहमति दी है लेकिन यह कैसे सम्भव होगा इस पर कई सवाल खड़े किये हैं। कुछ युवाओं का कहना था कि हमारे देश में लगभग 30 करोड़ परिवार हैं। प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को यदि सरकारी नौकरी देते हैं तो सरकार पर प्रत्येक परिवार के लिए प्रतिमाह लगभग 20,000/- (बीस हजार रुपये) का प्रबंध करना होगा। अर्थात् सरकार पर लगभग 30 करोड़ × 20 हजार यानी 600 हजार करोड़ रुपये प्रतिमाह का अपने बजट में प्रबंध करना होगा। यह कैसे सम्भव होगा?

कुछ युवाओं का कहना था कि इस व्यवस्था से तो पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। यदि अनपढ़ को पक्की नौकरी मिलेगी तो आदमी पढ़ेगा ही क्यों?

कुछ युवाओं ने कहा कि यह तो सही है कि पढ़े लिखे को कुछ भी हुनरमंद काम नहीं आता और यह केवल अपनी बातों की चापलूसी के आधार पर नौकरी पा लेते हैं। लेकिन ज्यादातर अनपढ़ लोग तो हुनरमंद होते हैं। जैसे किसान अपने ज्ञान के आधार पर अनाज पैदा करके देश के लोगों के भोजन की व्यवस्था देता है फिर भी उसे ज्ञानी नहीं समझा जाता और उसे पक्की नौकरी देने की बात नहीं उठती है। इसी प्रकार कोई भी कारीगर वर्षों की अपनी तपस्या के आधार पर ज्ञान और हुनर प्राप्त करता है। अपने ज्ञान के बल पर वह विभिन्न जीवनोपयोगी वस्तुएं देश के लोगों को देता है। जैसे कपड़ा, जूता, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के आयटम, लकड़ी के फर्नीचर, लोहे के जाली-फाटक और असंख्य ऐसी वस्तुएं कारीगर ही देता है। कारीगर को अनपढ़ कहकर हम उसके ज्ञान को अपमानित करते हैं और उसे पक्की नौकरी देने की बात पर कभी भी गंभीर नहीं होते हैं। आदिवासियों का जंगल में रहने का ज्ञान और छोटे-छोटे दुकानदारों का पूरे समाज को कोने-कोने तक वस्तुएं पहुंचाने का काम भी किसानों कारीगरों के समान ही एक ज्ञानवान कार्य होता है। घर की महिलाओं के ज्ञान की तो सबसे ज्यादा इज्जत करना चाहिए। बच्चों के लालन-पालन से लेकर बड़े बुजुर्गों को भोजन देना और पूरे घर को व्यवस्थित चलाना उसी के ज्ञान से सम्भव होता है। ऐसे ज्ञानवान लोग यानि पूरा लोकविद्याधर समाज यदि अपनी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक पक्की नौकरी की बात करते हैं तो यह उनका जायज अधिकार होना चाहिए।

कुछ एक युवाओं ने कहा कि यदि किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटे-छोटे दुकानदार और महिलाओं को यदि पक्की नौकरी मिल जाती है तो अपना काम ही बंद कर देंगे जैसे आज पढ़े लिखे लोग जो सरकारी नौकरियों में रहते हैं काम ही नहीं करते।

इस बात पर कुछ युवाओं ने यह तर्क दिया कि यदि किसान या कारीगर को पक्की नौकरी में से जो पैसा मिलेगा वह निश्चित तौर पर

... शेष पृष्ठ 4 पर

लोकविद्याधर समाज की ज्ञान की राजनीति

उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा तीनों को ही मुंहकी खानी पड़ी। समाजवादी पार्टी का शासन पहले भी रह चुका है। इसलिए ये जनता के पक्ष में कुछ करेंगे ऐसा नहीं है यह भी अधिकतर लोग समझते हैं। भ्रष्टाचार की स्थितियों में कोई बदलाव आयेगा, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं रखता। मुलायम सिंह की जगह उनके पुत्र अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने से कुछ बातों में अंतर जरूर आ सकता है, लेकिन नीतियों के स्तर पर कुछ नया देखने को मिलेगा इसके कोई संकेत नहीं मिलते। लैपटॉप, टेब्लेट और बेरोजगारी के भत्ते के वादे भी सिकुड़ना शुरू हो गये हैं, कहां जा कर स्थिर होंगे यह कहना मुश्किल है, हालांकि नई सरकार ने शिक्षा की नीति और व्यवस्था में किसी बदलाव की बात नहीं की है। हो सकता है कि और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जायें, लड़कियों की शिक्षा की सहूलियतें बढ़ा दी जायें, या फिर और साइकिलें, यूनीफार्म और बस्ते बंट जायें। तो फिर क्या बदला है? इस चुनाव ने किन बातों को रेखांकित किया है?

समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों की पार्टी के नाम पर जानी जाती है। पिछड़े वर्गों की पार्टियों का उदय तीन प्रमुख संदर्भों में देखा जा सकता है - किसानों का अपने हितों के प्रति जागरूक और संगठित होना, राजनीति का विकेन्द्रीकरण (प्रांतीय राजनीतिक दलों का उदय) और सामाजिक न्याय (विशेषकर आरक्षण) की राजनीति। 1960 के दशक से साफतौर पर इस प्रक्रिया को आकार लेते देखा जा सकता है। 1967 में नौ राज्यों में कांग्रेस की हार, 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और 1989 में फिर से केन्द्रीय सत्ता से कांग्रेस का बाहर होना, ये पिछड़े वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक दखल के विकास में मील के पत्थर रहे हैं। इस दौर में बड़े-बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, लगभग हर राज्य में सशक्त प्रांतीय दलों का उदय हुआ है और वे सत्ता पर काबिज हुए हैं तथा सामाजिक न्याय के वैचारिक आग्रह तथा आरक्षण ने सार्वजनिक दुनिया में पिछड़े वर्गों के दबदबे को बहुत बढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इन्हें अब अपना अगला राजनैतिक कदम तय करना है। यह अगला कदम लोकविद्याधर समाज की पहचान और उसके ज्ञान की ताकत के बल पर ही लिया जा सकता है।

वैश्वीकरण और कम्प्यूटर इंटरनेट के दबदबे में अब दो दशक से *जो* दुनिया आकार ले रही है, उसमें 'ज्ञान की राजनीति' अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाती जा रही है। नये वर्गों का जन्म हुआ है और पश्चिम के विचार अधिक तेजी से हावी होने लगे हैं। जिन शहरी मध्यम वर्गों को पिछड़े वर्गों की राजनीति के दौरान पीछे हटना पड़ा था, वे फिर आक्रामक रुख अपना रहे हैं और अपने खोये हुए स्थान (जो इन्हें अंग्रेजी काल में मिला था) को वापस पाने के लिए आतुर हैं। 'इण्डिया अगेन्स्ट करप्शन' इसका उदाहरण है। दूसरी ओर प्रांतीय दलों की यह स्थिति बनती चली जा रही है कि वे दिल्ली की सत्ता के साथ समझौते को राजकाज की एक शर्त मान चुके हैं। इस मनोदशा और परिस्थिति से बाहर निकले बगैर कोई नई नीतियां अपना पाना तो दूर, वे पिछले दशकों में आये परिवर्तन को बचा पाने में भी सक्षम नहीं हो सकेंगे। खेल तो तभी बचता है और तभी बनता है, जब ये खुद को पिछड़े वर्गो की ताकत के बजाय लोकविद्याधर समाज की ताकत के रूप में देखें और ज्ञान की एक नई राजनीति खड़ी करें।

यह ज्ञान की राजनीति तो तभी बनती है जब यह पहचाना जाय और इस बात को खुला समर्थन दिया जाय कि किसान और कारीगर ज्ञानी हैं। वे तमाम लोग जो इस देश में 80 फीसदी से ज्यादा हैं, अपने ज्ञान के बल पर अपनी दुनिया चलाते हैं। किसान, पशुपालक, बुनकर, मल्लाह, लोहे और लकड़ी का काम करने वाले, मिट्टी के कारीगर, घर बनाने वाले, बिजली, टी. वी., मोबाइल, मोटर साइकिल और तमाम किस्म का मरम्मत का काम करने वाले, ठेलों-गुमटी पर धंधा करने वाले, गांव-गांव में फैले कलाकार, जंगलों के जानकार आदिवासी और इन सभी के घरों की महिलाएं ये सब कभी कॉलेज नहीं गये होते, ये सब अपना सब काम अपने ज्ञान के बल पर करते हैं। ये सब पिछड़े वर्गों और दलित वर्गों के लोग हैं। इन्हें आज भी न समाज में सम्मान है और न इनकी सुनिश्चित पक्की आय ही होती है। इनके ज्ञान को **लोकविद्या** कहा जाता है और इस पूरे समाज को **लोकविद्याधर समाज**। **'पिछड़ा' और 'दलित' की भाषा का अंत होने का समय आ गया है। एक नई ज्ञान की राजनीति बनानी होगी जो पूंजी की राजनीति की भाषा से अपने को मुक्त करेगी।**

यह राजनीति हर व्यक्ति की आय पक्की और सुनिश्चित करने के दावे के साथ खड़ी होती है। चूंकि हर व्यक्ति ज्ञानी है, लोकविद्या का स्वामी है, इसलिए हर व्यक्ति को जो काम उसे आता है उसी के बल पर पक्की आय की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा नीति और आर्थिक व्यवस्थायें दोनों में बड़े बदलाव की जरूरत होगी। आजादी के बाद की बदलाव की राजनीति को अब यही दिशा लेनी होगी। **पिछड़े वर्गो और दलित वर्गो के नेताओं को दिल्ली के ख्वाब देखना बंद करना होगा, आपस में दोस्ती करनी होगी, लोकविद्याधर समाज की एकता के मार्फत ज्ञान की एक नई राजनीति खड़ी करनी होगी।** यही गांधी का रास्ता है और यही इस देश का रास्ता हो सकता है।

•

गुलजार दिल्ली बनाम अविरल गंगा

पिछले कई महीनों से एक 'अविरल गंगा अभियान' बहुत तेज हुआ है। हिमालय के क्षेत्र में गंगा नदी पर बारह बांध बनाये जा रहे हैं। टिहरी में एक बहुत बड़ा बांध पहले से बना हुआ है। अब इन नये बांधों के चलते कई जगह, कई किलोमीटर के लिए नदी सूख जायेगी। बांधे हुए पानी को जगह-जगह सुरंगों में डालकर भरपूर ऊंचाई से गिराने का इंतजाम किया जा रहा है जिससे बिजली बनायी जा सके। सरकार के इस कार्यक्रम के खिलाफ गंगा नदी से ऐसी छेड़छाड़ न करने के इस अविरल गंगा अभियान का नेतृत्व प्रो. जी. डी. अग्रवाल, जो अब स्वामी सानंद हैं, कर रहे हैं। प्रो. अग्रवाल आई.आई.टी. कानपुर में सिविल व पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं। केन्द्रीय पर्यावरण आयोग के सदस्य रहे हैं और गंगा नदी के बारे में बहुत बड़े जानकार हैं। इस विषय के विशेषज्ञों में बड़ा सम्मान रखते हैं। अब वयोवृद्ध अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया है तथा अपने उपवास एवं त्याग के जरिये गंगाजी पर हो रहे सरकारी हमले के व्यापक विरोध को एकजुट करने में लगे हैं। सरकार इस विषय में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वोच्च गंगा प्राधिकरण की बैठक में इस पर विचार तक नही किया गया।

टिहरी बांध बनने के समय से ही गंगाजी पर बांध बनाने का बड़ा विरोध होता रहा है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने गांधीवादी तरीकों से टिहरी बांध की खिलाफत को दशकों तक दिशा दी। लेकिन सरकार ने एक न सुनी और बांध बना ही दिया। गंगाजी से छेड़छाड़ का विरोध समग्र तर्क प्रस्तुत करता रहा है। पर्यावरण, विस्थापन, हिमालय क्षेत्र में भूकम्प, बांधों के टूट जाने की संभावना, नीचे के क्षेत्रों में बाढ़, सामान्य परिस्थितियों में मैदानी इलाकों में पानी का बेहद कम हो जाना, गंगा नदी के पानी के अद्‌भुत जैविक गुणों का ह्रास, तीर्थों पर विपरीत प्रभाव तथा बहुत बड़े जन समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस जैसे तर्क शुरू से ही दिये जाते रहे हैं। सरकार की ओर से इन तर्कों का कोई ठीक जवाब कभी भी नहीं दिया जा सका है। बस, सरकार अपनी योजनाएं लागू करने पर आमादा है। उनके समर्थक और वे खुद बिजली उत्पादन की आवश्यकताओं का सहारा लेते रहे हैं और सारे तुरंत के, दूरगामी और सभ्यतागत नुकसानों को विकास की कीमत के रूप में पेश करते रहे हैं। अबकी बार स्वामी सानंद का अभियान तेज होने पर विशेषज्ञों ने यह साफ तौर पर कहा कि सरकार हिमालय क्षेत्र में बांध बनाना कत्तई बंद नहीं करेगी क्योंकि इससे दिल्ली का बिजली-पानी जुड़ा हुआ है। दिल्ली में बिजली और पानी इफरात रहे, दिल्ली गुलजार रहे इसके लिए गंगाजी पर इतने सारे बांध बनाने ही पड़ेंगे तो सवाल सीधा है—गुलजार दिल्ली बनाम अविरल गंगा के बीच किसे चुनना चाहिये, इस देश के लिये क्या जरूरी है- पैसे वालो की ऐशो-आराम की ज़िन्दगी या करोड़ो लोगों की ज़िन्दगी और सभ्यता।

इसीलिए किसी भी दल ने अविरल गंगा अभियान का समर्थन नहीं किया है। पूरी की पूरी राजनीति एक कटघरे में खड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा 'लोकतंत्र' एक कटघरे में खड़ा है। जो इस विकास को विनाश मानते हैं, जो बहुजन समाज के उद्धार के लिए संघर्षरत हैं, जो इस समाज और अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन का झण्डा ऊंचा करने वाले सभी कार्यकर्ताओं द्वारा इस पूरी राजनीति को नकारा जाना जरूरी है। इस राजनीति को नकारने का अर्थ है दिल्ली को नकारना। दिल्ली को नकारे बगैर गंगा को अविरल रखना सम्भव नहीं है।

•

... पृष्ठ 3 का शेष

ग्राम पालडि में लोकविद्या युवा शिविर

अपने कार्य में लगायेगा। खाद, बीज और कच्चे माल की व्यवस्थाओं को वह व्यवस्थित करेगा। दूसरा न तो उसे काले पीले कार्डों की जरूरत होगी और न ही सरकारों द्वारा भिखारियों को देने जैसी मुफ्त में दी जाने वाली किसी योजना की जरूरत होगी।

युवा शिविर में वाराणसी से पधारे विद्या आश्रम सारनाथ के श्री सुनील सहस्रबुद्धे और श्रीमती चित्रा सहस्रबुद्धे ने भी युवाओं से चर्चा की। लोकविद्याधर समाज के पास बहुत मूल्यवान ज्ञान होता है। विश्वविद्यालयीय ज्ञान या धर्म के ज्ञान या कम्प्यूटर इंटरनेट के ज्ञान से यह ज्ञान किसी भी मायने में कम नहीं है। लोकविद्याधर समाज अपनी लोकविद्या के बल पर एक नई दुनिया बनाने जा रहा है। पूरे देश को चलाने का काम लोकविद्याधारी ही कर रहे हैं। धर्म या पूंजी की राजनैतिक व्यवस्थाओं ने पूरे देश में लोकविद्याधारी के ज्ञान को सम्मान देकर बराबरी का दर्जा कभी नहीं दिया है। आज पूरी दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में भूचाल आ गया है और लोकविद्याधर को एक नई दुनिया गढ़ने का दावा पेश करने का समय आ गया है।

श्रीमती चित्रा सहस्रबुद्धे ने लोकविद्या जन आंदोलन में युवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है इस बात पर जोर दिया। यह लोकविद्याधरों का ज्ञान आंदोलन है और लोकविद्याधर अपने ज्ञान के बल पर ही संगठित होंगे और इस एकता में ही हर समस्या का हल है और मुक्ति का रास्ता है।

युवा शिविर में आये युवाओं ने लोकविद्या जन आंदोलन के मुद्दों पर सहमति जताते हुए एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया।

•

विश्वविद्यालय-ज्ञान का दीवालियापन

केवल बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सरकारी नीति पर एक उड़ती नजर भी डालें तो ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो हमें गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जरा इन पर गौर करें—

1. पांच लाख गांवों के हर घर में बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और रसोई के समय शाम को 6 से 10 बजे तक बिजली काटकर मॉल, हवाई अड्डे और महानगरों के बाजार जग-मग चमकें और भरपूर ए. सी. का इस्तेमाल करें, इसके लिये दी जाये।
2. जंगलों, आदिवासियों के गांवों और किसानों की जमीनों को तबाह करके वह बिजली बने जो बड़े-बड़े कारखानों और कम्प्यूटरों को कभी बंद न होने दे और महानगरों को बिना किसी कटौती के जग-मग रखे।
3. गंगा पर कई बांध बनाकर उसका पानी सुखा दिया जाय क्योंकि लगातार विस्तार पाती दिल्ली को यह पानी चाहिये।
4. नर्मदा को बांधकर आदिवासियों के गांव उजाड़ दिये जाय। किसलिए तो मध्य प्रादेश के सबसे बड़े आधुनिक और विस्तार पाते शहर इन्दौर को इस पानी की जरूरत है।
5. जब दुनियाभर में परमाणु ऊर्जा कारखाने बंद किये जा रहे हों हमारे देश में उन्हें खूब विस्तार दिया जाय क्योंकि वहां के बंद होते संयंत्रों को बाजार चाहिए और हमारे यहां के शासन-प्रशासन को कमीशनों की मोटी रकम।
6. हम उच्च शिक्षा की ओर अपनी दौड़ तेज करते चले जा रहे हैं। जब दुनियाभर में इस बात का हल्ला है कि उच्च शिक्षा इतनी महंगी है कि उसमें बहुत कम लोग ही जा सकते हैं और वह पूंजी और बाजार की सेवा के अलावा और कुछ कर नहीं सकती।
7. आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की अमेरिका और यूरोप में यह स्थिति है कि वहां रहने वाले भारतीय भारत आकर अपना उपचार कराना पसंद करते हैं फिर भी हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को उन्हीं की तर्ज पर क्यों संगठित करते चले जा रहे हैं?

सोच के दिवालियापन का आधार ज्ञान के दिवालियेपन में होता है। जिन नीतियों के विनाशकारी प्रभाव जगजाहिर हैं उनका विकल्प भी हम नहीं सोच सकते यह उस ज्ञान और उस शिक्षा के चलते है जो विश्वविद्यालय में बसते हैं और जिसे हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यहीं पर बदलाव की जरूरत है। किसानों और कारीगरों के ज्ञान की पुनर्प्रतिष्ठा के बगैर न हमारे पास कोई रास्ता बचेगा और न दुनिया में किसी और के पास।

•

किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटा दुकानदार एक हों

क्योंकि

सूचना युग में कम्प्यूटर-इंटरनेट और वैश्वीकरण मिलकर किसानी, कारीगरी, छोटी दुकानदारी को उजाड़ रहे हैं, मज़दूरी को घटा रहे हैं।

कैसे?

1. **इनके श्रम को बाजार में कम दाम देकर**
2. **इनके ज्ञान यानि लोकविद्या को लूटकर**
3. **शिक्षा को महंगी बना कर व इन्हें नये ज्ञान से वंचित कर**

आइए

1. **लोकविद्या के बल पर जीविका के अधिकार का दावा करें।**
2. **सूचना युग में श्रम और ज्ञान की लूट को रोकने के उपाय खोजें।**
3. **बाजार और ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोषण की समझ और विरोध को आकार दें।**

लोकविद्या पंचायत के पाठकों से

- **वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 50/-**
- **वेतन पाने वालों से कम से कम रु. 100/- प्रति वर्ष अपेक्षित है।**
- **आजीवन सदस्यता रु. 1000/-**
- **अपने क्षेत्र के लोकविद्याधरों की समस्यायें, संघर्ष एवं संगठनों के बारे में अवश्य लिख भेजें।**

सम्पर्क फोन

+91-9369124998, +91-9838944822

लोकविद्या जन आंदोलन (लो.ज.आ.)

संयोजन समिति व सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक

18 मार्च, 2012, सेवाग्राम, वर्धा (महाराष्ट्र)

नवंबर 2011 में वाराणसी में हुए लोकविद्या जन आंदोलन के प्रथम अधिवेशन में एक लो. ज. आ. संयोजन समिति और एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इन समितियों की संयुक्त बैठक गांधीजी के सेवाग्राम आश्रम में 18 मार्च को हुई। हैदराबाद, वर्धा, नागपुर, पुणे, वलसाड़, इन्दौर, धार, सिंगरौली, वाराणसी, गया, और दरभंगा के साथियों ने भाग लिया। सभी स्थानों से आये लोगों ने अपने यहां लो.ज.आ. की गतिविधियों और योजनाओं के बारे में बताया।

दरभंगा : विजय कुमार ने 31 मार्च - 1 अप्रैल को दरभंगा में आयोजित बिहार लो. ज. आ. अधिवेशन की तैयारियों के बारे में बताया और सबको वहां आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल जिलों से लोगों की भागीदारी होगी तथा लोकविद्या के आधार पर जल (नदी) व्यवस्था तथा लोकविद्या के आधार पर सबको पक्की नौकरी प्रमुख मुद्दे होंगे। पूरे देश को श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले इन क्षेत्रों के लिए लोकविद्या के आधार पर समाज के पुनर्संगठन का दावा एक वरदान साबित होगा।

गया : रवीन्द्र और प्रमिला पाठक ने गया क्षेत्र में लोकविद्या आधारित पारम्परिक जल व्यवस्था के बारे में बताया। इस मुख्य मुद्दे पर किसान संगठन बनाने की चुनौतियां सामने रखी और कहा कि ज्ञान क्षेत्र में लोकविद्या के दावे के लिए यह एक अत्यन्त उपयुक्त क्षेत्र है।

वाराणसी : लक्ष्मण प्रसाद और दिलीप कुमार ने वाराणसी में बढ़ाये जा रहे रचनात्मक और संगठनात्मक कार्यों की चर्चा की। यह बताया कि भारतीय किसान यूनियन का संगठन कार्य वाराणसी परिक्षेत्र में लोकविद्या दृष्टिकोण से ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किसान संगठन में लोकविद्या का विचार चर्चा का विषय बन चुका है। ठोस रूप में वाराणसी में लोकविद्या आश्रम के निर्माण का प्रयास है। गांव-गांव में युवाओं के बीच लोकविद्या के आधार पर पक्की नौकरी के शिविर आयोजित किये जा रहे हैं और विस्थापन विरोधी संघर्षों में विस्तृत भागीदारी की जाती है।

सिंगरौली : लक्ष्मीचंद दुबे और अवधेशजी ने सिंगरौली की वास्तविकताओं में लोकविद्या दृष्टिकोण से कैसे नई पहल अस्तित्व में आयी है, यह बताया। उन्होंने बताया कि सिंगरौली में 9-10 अगस्त को लोकविद्या जन आंदोलन के अधिवेशन की तैयारी चल रही है। ऊर्जा नीति में वितरण की नीति को वरीयता हो, विस्थापन से पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है यह समझा और माना जाय और इस किसान-आदिवासी क्षेत्र की समस्या का हल तभी हो सकता है जब हर परिवार में एक पक्की नौकरी हो ये बातें अधिवेशन के प्रमुख विषय होंगी। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को अधिवेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

इन्दौर : संजीव भाई ने इन्दौर के क्षेत्र में ली जा रही लोक पहल के बारे में बताया। उन लोगों द्वारा गांव-गांव चलाये जा रहे अभियानों के बारे में बताया। बाजार मोड़ो - लोकविद्या बाजार बनाओ, विस्थापन का विरोध करो और लोकविद्या के आधार पर पक्की आय की व्यवस्था मांगो, ये वहां के अभियान के मुद्दे हैं। इन्दौर को मध्य प्रदेश और आसपास के बड़े क्षेत्र के सबसे बड़े शैक्षणिक, व्यापारिक और औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुम्बई-दिल्ली व्यापारिक कारिडोर शहर के पास से ही गुजरता है। नतीजे स्वरूप पूरा इलाका विस्तृत तहस-नहस का शिकार है। किसान और आदिवासी अपनी जिन्दगी की बहाली लोकविद्या के अलावा और कहीं नहीं पा सकते, इसी के इर्दगिर्द वहां का लो. ज. आ. संगठित हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दिसंबर तक वहां पर लो. ज. आ. का एक बड़ा अधिवेशन संगठित किया जा सकेगा।

हैदराबाद : नारायण राव और कृष्णराजुलु ने लोकविद्या प्रपंचम नाम से प्रकाशित किये जा रहे तेलुगु पत्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस साल गर्मियों में विजयवाड़ा में लोकविद्या अधिवेशन का आयोजन होगा। तारीखों को जल्दी ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

सभी स्थानों के बारे में चर्चा के दौरान यह उभरकर आया कि लोकविद्या के आधार पर पक्की आय की व्यवस्था, जिसे जो आता है उसके बल पर नौकरी और सरकारी तनख्वाहों के बराबर तनख्वाह, यह सभी जगह समान रूप से लागू होता है। लोकविद्याधर समाज सभी जगह बड़े पैमाने पर विस्थापित किया जा रहा है, अपनी जमीनों से, रोजगार और धंधों से उसे उजाड़ा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जवाब इसी बात को खड़ा करने में है कि हर परिवार के पास पक्की आय की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक सरकारी नौकरी के बराबर का पैसा हर परिवार में हर महीने आना चाहिए। लोकविद्या जन आंदोलन इन्हीं परिवारों का ज्ञान आंदोलन है जो अपने ज्ञान के बल पर अपनी खुशहाली के दावे को इस जमाने के सार्वभौम दावे के रूप में पेश करता है।

सभी स्थानों से आये साथियों ने प्रकाशन को महत्त्वपूर्ण माना और अपने-अपने स्थानों से लो. ज. आ. को आगे बढ़ाने के लिए पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, पर्चों, पोस्टर आदि के प्रकाशन को बढ़ावा देने की बात कही।

आने वाले दिनों में दरभंगा और सिंगरौली अधिवेशनों में जोर भरने की हामी के साथ बैठक पूरी हुई।

•

लोकविद्या जन आंदोलन का मीडिया कैसा हो ?

मगन सिंह बघेल

विसर्जन आश्रम इन्दौर, दिनांक 25 मार्च, 2012 को मीडिया की भूमिका पर एक बैठक आयोजित की गयी। किसी भी जन आंदोलन में लोगों की बात को बहुसंख्य लोगों तक पहुंचाकर और आंदोलन की मूल भावनाओं को बिना तोड़े-मरोड़े कैसे रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित किया जा सकता है, इस बात पर मीडिया की भूमिका स्पष्ट होना चाहिए। मुख्य धारा के मीडिया का व्यावसायिक दृष्टिकोण है। क्या कोई वैकल्पिक मीडिया की बात की जाए? या विकल्प की बात न करते हुए एक ऐसी व्यवस्था को समझा जाए जिसमें लोकविद्याधारी आपस में एक दूसरे से कैसे गूंथे हुए? उनकी रिश्तों की दुनिया कैसी है? ये आपस में जानकारियों का आदान-प्रदान कैसे करते हैं? किसी जनभावना को अपने बिरादरी में कैसे संजोते हैं? क्या इनका कोई ऐसा तानाबाना है जो दिखाई नहीं दे रहा और जो वास्तव में है। इस ताने बाने पर दो सौ वर्षों के साम्राज्यों ने निरन्तर प्रहार किये हैं और हमें छिन्न-भिन्न करने का भरसक प्रयास करते रहे हैं। क्या इस ताने-बाने पर धूल की परतें चढ़ी हैं जिसे हटाकर, इसे पुनर्जिवित किया जा सकता है?

श्री अनिल त्रिवेदी, श्री किशोर गुप्त, श्री इन्द्रविक्रम, श्री दिनेश कोठारी, श्री संजीव कीर्तने ने अपनी अपनी बातें रखीं और मीडिया के किसी विकल्प को गढ़ने के बदले लोकविद्याधर समाज के ताने-बाने पर एक समझ बनाने पर जोर दिया। विद्या आश्रम सारनाथ से श्री सुनील सहस्त्रबुद्धे और श्रीमती चित्रा सहस्त्रबुद्धे ने भाषा, कला, दर्शन और लोकविद्या ताना-बाना पर अपनी बात रखी। 19-20 फरवरी को विद्या आश्रम में लोकविद्याधर समाज में आपसी संपर्क और संबंध की विधायें, नई तकनीकों का लोकविद्या ताना-बाना में प्रयोग, स्थानीय प्रयासों, सामुदायिक रेडियों का इस्तेमाल, संघर्षों को जोड़ने में लोकविद्या ताना-बाना की भूमिका और लोकविद्या ताना-बाना का समाज में स्थान, ठोस रूप में यह कितना लोकविद्याधर समाज का अंग होगा और कितना प्रतिनिधि ऐसे मुद्दों पर बात की गयी।

श्रीमती चित्रा सहस्त्रबुद्धे ने लोकविद्या जन आंदोलन की दृष्टि से छोटे-छोटे स्थानीय प्रकाशनों को बढ़ाते हुए उनको आपस में जोड़ने की विधाएं एवं व्यवस्थाएं विकसित करने की बात कही। यह भी बात हुई कि लोकविद्या ताना-बाना को यदि लोकविद्याधर समाज की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में देखा गया तो इस ताना-बाना को उस समाज के बाहर और उसके नियंत्रणों से स्वतंत्र अस्तित्व को सैद्धांतिक मान्यता मिलती है और यह किसी भी दूरगामी दृष्टि से मान्य नहीं हो सकता। बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि माह मई में इन्दौर में लोकविद्या ताना-बाना पर एक चिन्तन परिचर्चा का आयोजन किया जायेगा।

•

लोकविद्याधर समाज के चार बड़े दुःख

1. **लोकविद्या यानि उनके ज्ञान को ज्ञान ही नहीं माना जाता।**
2. **आज का बाजार उनके श्रम और ज्ञान का जायज मूल्य नहीं देता।**
3. **राष्ट्रीय संसाधनों जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, वित्त आदि का सबसे छोटा हिस्सा इन्हें दिया जाता है।**
4. **इन्हें इनके जीवनयापन के कार्यों, संसाधनों और रहने के स्थानों से लगातार विस्थापित किया जा रहा है।**

सिंगरौली के लोगों की चिंतायें

सासन पॉवर प्रोजेक्ट में विगत प्रभावित विस्थापित एवं प्रदूषण को लेकर सृजन लोकहित समिति द्वारा 15 मार्च 2012 को शासन गांव में विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें सासन, सिद्धी खुर्द आदि प्रभावित गांवों के लोगों के अलावा पर्यावरण विद पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्रमिक नेता एवं परियोजना प्रभावित लोगों से बातचीत में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए जिनकी ओर से स्थानीय प्रशासन एवं परियोजना अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं।

गोष्ठी में चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि सिद्धी खुर्द निवासी 50 वर्षीय सुदर्शन रजक का आज तक कुछ भी पता नही चला जबकि उस की गुमशुदगी की नामजद रिपोर्ट बैढ़न थाने में लिखाई गई थी। सुदर्शन रजक के पुत्र महेन्द्र रजक ने बताया कि 19 मई 2005 को सुदर्शन की मझली पतोहू केवलीपती दौड़ते हुए उनके पास आई और बोली कि अधिकारी लोग सब घर गिराये दे रहे हैं। सुदर्शन ने घटना स्थल पर जाकर विरोध किया कि जब तक पुनर्वास की सुविधा नहीं दी जायेगी तब तक वे नहीं हटेंगे। परियोजना अधिकारी टी. एन. सिंह, व्ही. व्ही. सिंह सिक्योरिटी गार्ड आफीसर संग्राम सिंह ने बुरी तरह डांटा-फटकारा और जान से मरवा देने की धमकी दी, सुदर्शन रात को खाना खाकर बरामदे में सोया था और जब सुबह हुई तो घर वालों ने देखा कि वह घर पर नहीं है। कई दिनों तक उसकी खोजबीन की गयी लेकिन आज तक कहीं पता नहीं चल सका। सुदर्शन का गुम हो जाना लोगों के बीच आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि सुदर्शन को धरती निगल गई या कि आसमान उठा ले गया। पुलिस ने भी नामजद आरोपियों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया। इसी क्रम में युवा श्रमिक नेता सती प्रसाद एवं परियोजना में काम कर रहे श्रमिकों ने बताया कि यद्यपि मजदूरी श्रमिक के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित है। उच्च कुशल श्रमिक 297 रुपये, कुशल श्रमिक 256 रुपये, अर्ध कुशल श्रमिक 212 रुपये तथा अकुशल श्रमिक 175। लेकिन इस दर से मजदूरी न देकर सभी को 175 रुपये मजदूरी दी जाती है जबकि काम कुशल श्रमिक व हेल्पर का लिया जाता है। लेबर इस्पेक्टर सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आते रहते हैं, शिकायतों पर लीपा पोती करते हैं। गोष्ठी में बातचीत से यह भी तथ्य सामने आया कि जब कंपनियां काम शुरू करती हैं तो ग्रामीणों को तरह-तरह से लुभाया जाता है, झूठे वायदे किये जाते हैं। अपना काम निकालने के लिए कंपनियां ग्रामीणों से एग्रीमेंट भी कर लेती हैं पर जमीन कब्जा करने के बाद परियोजना अधिकारियों का सुर बदल जाता है। पुनर्वास की समुचित व्यवस्था किये बिना ही घर खाली कराये जाते हैं। इसी प्रकार दुर्घटना होने पर शुरू में तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है, कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, पर जैसे-जैसे दिन बीतते हैं उनकी कोई सुधि भी नहीं ली जाती।

लोकविद्या जन आंदोलन के कार्यकर्ता अवधेश ने कहा कि कैसे जिये बैगा? इस जनजाति की घटती संख्या सरकार के लिए भी चिन्ता का कारण है। जंगल-पहाड़ के भरोसे जीने वाली यह जनजाति बहुत सीधी-सरल होती है। सासन पॉवर परियोजना से प्रभावित गांव तियरा में बैगाओं की काफी संख्या है। ये लोग किसी भी कीमत पर गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन परियोजना की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि ये लोग गांव छोड़कर भाग जायें। इन्हें तरह-तरह से डराया धमकाया जाता है। गोष्ठी में कई लोगों ने हताशा भरे स्वर में कहा कि रिलायंस का 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया अब तक हम लोगों की क्या सुनवाई हुई? हम तो बाहर से ही चिल्लाते रहेंगे ये गेट बंद कर अपना काम करते रहेंगे। इसके जवाब में समाजवादी नेता लक्ष्मी चन्द्र दुबे ने कहा कि इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है जब तक वाजिब हक न मिलेगा, लड़ाई जारी रहेगी। आपने विन्ध्याचल पावर प्लांट का उदाहरण देते हुए कहा कि प्लांट बन जाने के बाद भी विस्थापितों को कलेक्टर श्रुतकीर्ति ने एक लाख 40 हजार का पैकेज अनुदान दिलवाया। संगोष्ठी में काशी प्रसाद शाह, मनोह शाह, रामसुन्दर वैश्य, राम सजीवन वैश्य, राजकुमार केवट, बाबूलाल रजक, शेषमन शाह, अरविन्द कुमार रजक, झुरई साहू, बृजलाल शुक्ला, रामप्रताप मिश्रा, रामसुभग शुक्ला आदि ने भी अपने विचार प्रकट किये।

•

ज्ञान एकजुटता और नये संघर्षों की कतार

लीना दोकुजोविच

आज शिक्षा और ज्ञान-उत्पादन समाज में बदलाव के प्रमुख स्थान हैं। एक तरफ इनमें उन बदलावों का केन्द्रीय तंत्र निहित है, और दूसरी तरफ यह जन साधारण को अकुशल मजदूरों में परिणत करते हैं। ज्ञान के पदार्थीकरण या शिक्षा में निजीकरण की ओर बदलाव के खिलाफ संघर्ष की भूमिका निर्णायक है, क्योंकि यह आज की सबसे गहरी प्रक्रियाओं में से एक पर वार होगा। श्रम के वैश्विक विभाजन एवं ज्ञान तक पहुंच के बीच की उभयनिष्ठ कड़ियों की व्याख्या व परीक्षण, सहभागिता और जिम्मेदारी को समझने के क्षेत्र में और दमन के वैश्विक स्वरूपों के खिलाफ पार—सामुदायिक एकजुटता बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यदि संकट की प्रचलित अवधारणा को पलट दिया जाये और ज्ञान को नीति निर्धारण के केन्द्र में स्वीकृत किया जाये तो हमें ज्ञान की भूमिका को निश्चित तौर पर पलट देना होगा ताकि इसे एक मूलभूत ताकत के रूप में देखा जा सके।

हाल के वर्षों में ज्ञान के इर्द-गिर्द दुनिया भर में कई आंदोलन खड़े हुए। उदाहरण के लिए यूरोप में 2008-2010 के दौरान चले विश्वविद्यालयीय संघर्षों को खासतौर पर बोलोना प्रक्रिया द्वारा किये जा रहे निगमीकरण के पक्षधर सुधार ने ही पैदा किया। दशकों से विश्वविद्यालय के नव उदारीकरण का विरोध होता रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऊंची फीस और छात्रों को कर्ज की व्यवस्था है, इन देशों में शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान में कटौती और कर्ज के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन अपने आकार, जोश, सघनता और आपस में संचार और संबंध आदि के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय सीमाओं से निकल कर संबंध बनाये गये हैं तथा शिक्षित बेरोजगारों और गैर मान्यता प्राप्त कामगारों की स्थितियों के साथ समानता पहचान रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और विरोध प्रदर्शनों, यथा 2010 में वियना में यूरोपीय उच्च शिक्षा क्षेत्र के खोले जाने के उत्सव के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत ने संघर्ष के नये स्थानों का सृजन और विस्तार किया है। जबकि हाल के वर्षों में हुए विश्वविद्यालयीय विरोधों को मीडिया ने बाद के वर्षों में हुए दूसरे विद्रोहों की तुलना में काफी कम तवज्जो दी और जबकि अधिकांश लोग शायद मीडिया में हुई गम्भीर किन्तु काफी कम चर्चा के कारण, इन विश्वविद्यालयीय विरोधों को अपरिहार्य बोलोना प्रक्रिया के क्रियान्वयन अथवा उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ असफल मानते हैं, परन्तु यह खासतौर पर ध्यान देने वाली बात है कि वे आंदोलन अभी खत्म नहीं हुए हैं। इन्होंने केवल अपना स्थान बदला है। इन संघर्षों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए अथवा भुलाया नहीं जाना चाहिए। इन आंदोलनों ने अनेक महत्त्वपूर्ण सबक दिये हैं तथा उन्हें एक जीवन्त और लचीली ताकत के रूप में देखने की जरूरत है।

फरवरी 2011 में, ''खर्च में कटौती के खिलाफ विश्वविद्यालयीय संघर्ष'' नामक ''शिक्षा में संघर्ष'' की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक पेरिस में की गयी। यह बैठक तुनीसिया की क्रांति के तत्काल बाद हुई, जिसने मीडिया के ध्यानाकर्षण और संघर्ष में बदलाव और एकजुटता के मामले में बड़ी भूमिका निभाई। इस बैठक में भाग लेने के लिए चले कई तुनीसियाई आंदोलनकारी यूरोपीय संघ की सीमा पर रोक लिए गए और पेरिस नहीं पहुंच पाने के कारण इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके। प्रदर्शन जारी रहा और कुछ तुनीसियाई छात्र शामिल भी हुए। इन तुनीसियाई छात्रों के द्वारा एक घोषणा-पत्र जारी किया गया, जिसमें इस बैठक में निहित संघर्ष के बिन्दुओं को पूरे मघ्रेब (उत्तरी अफ्रीका) देशों में फैल चुके तुनीसियाई विद्रोह से जोड़ कर देखे जाने की मांग की गयी। इसके उपरान्त एक घोषणा-पत्र जारी हुआ जिसमें सम्पूर्ण भूमध्य सागर के दोनों ओर के क्षेत्रों में संघर्षों की एकजुटता के महत्त्व की वकालत की गयी। 29 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक छात्र, बेरोजगार, अनियत/अनिश्चित कामगार और यूरोप तथा उत्तर अफ्रीका के सक्रिय कार्यकर्ता तुनीसिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक रेस्यु दे ल्युट (फ्रेंच नाम, जिसका हिन्दी अर्थ होता है—संघर्षों का ताना-बाना) में शामिल हुए, ताकि अपने ज्ञान को साझा किया जाए और आपसी समन्वय के साथ संघर्ष किया जाय, बयान में यह दावा किया गया कि : पिछले कुछ महीनों में सम्पूर्ण उत्तरी अफ्रीका में फैल चुके संघर्षों ने पूरी दुनिया को सम्बोधित किया। दुनिया भर के आर्थिक संकट के संदर्भ में देखा जाये तो, बेन अली या मुबारक के तख्तापलट और यूरोप के संघर्ष के कई कारण आपस में समान अथवा उभयनिष्ठ हैं। हम अपने वर्तमान दुःख के खिलाफ और मुक्ति की तथा अपनी सामूहिक सम्पत्तियों को फिर से हासिल करने की प्रक्रियाओं के मार्फत नये सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण के लिए क्रांति कर रहे हैं। ये संघर्ष उन स्थानों का निर्माण कर रहे हैं जिन्हें सत्ता लगातार खण्डित करने और दबाने की कोशिश करती रही है।

मघ्रेब देशों में फैले विद्रोह को मीडिया के माध्यम से मिले भारी ध्यानाकर्षण ने दुनिया भर में हो रहे दूसरे आंदोलनों को काफी प्रोत्साहित किया। ''वाल स्ट्रीट पर कब्जा करो'' से लेकर लुब्जाना के ''बोज जा'' तक, सार्वजनिक स्थानों, वित्तीय केन्द्रों पर डेरा डालने अथवा कब्जा करने जैसे आंदोलन दुनिया भर में हुए। 15 अक्टूबर 2011 को वैश्विक अभियान दिवस मनाया गया जिसमें आज तक की सबसे बड़े पैमाने की और सबसे बड़ी संख्या में भागीदारी हुई। जबकि मीडिया ने कई संघर्षों के शुरू होने के समय और फैलने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इनमें जो संचार और समानताएं विकसित हुईं वे इनके द्वारा एक-दूसरे से सीखने और आपस में संचार की एक लम्बी प्रक्रिया का नतीजा है। इन संघर्षों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपों में ढलने के साथ-साथ इस बारे में समझ विकसित हुई कि किस प्रकार साझा संघर्ष के तमाम मुद्दे आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक बदलाव अभी प्रक्रिया में है, किन्तु अधिकांश मामलों में यह किसी सोची-समझी कोशिश का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द-गिर्द की लगभग एक समान परिस्थितियों के खिलाफ हो रही प्रतिक्रिया के रूप में हैं।

संकटों के आपस में जुड़ाव का उपयोग संघर्षों को व्यापक करने में होना चाहिए, क्योंकि संकटों का पृथक्करण संघर्ष को खंडित करने जैसा है। निगमित विश्वविद्यालयों के खिलाफ लड़ाई, बैंकों के खिलाफ लड़ाई का एक हिस्सा है। बैंकों के खिलाफ लड़ाई जमीन की लूट के खिलाफ लड़ाई का एक हिस्सा है। अतः इन मुद्दों की जटिलता को समझना जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इनकी समानता, सहभागिता अथवा विभेद और वर्तमान में वैश्विक सम्बन्धों का उलझाव समझने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना जरूरी है। जबकि यह 'संकट' कई ऐसी नीतियों का संचालन कर रहा है जिनका ज्ञान-उत्पादन में हस्तक्षेप बढ़ाना ही मूल उद्देश्य है, हम जैसे सांस्कृतिक कार्यकर्ता, सामाजिक तौर पर सक्रिय लोग और बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि असल सामाजिक संकट में दखल दें, इसे समझें कि पूरी दुनिया में चल रही विस्थापन की प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार हमारी पृथ्वी को प्रभावित किया जा रहा है, और यह देखें कि 'शिक्षा में संकट' वास्तविक रूप में कहां है?

वित्तीय संकट अथवा आर्थिक स्थिति को प्रशस्त संघर्ष के केन्द्र में रखा जाना संघर्ष के असुरक्षित होने का बोध कराता है। ऐसा कोई प्रभावी संघर्ष नहीं हो सकता, जो एक ऐसे ढांचे में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करता है, जो ढांचा न्यायोचित रूप से स्वयं को जारी न रख सके। यह विभिन्न संघर्षों को विखण्डित करता है, भले ही वे आपस में सघनता से जुड़े हों। एक ऐसी संरचना में जहां संकट ही कारण है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था प्रभाव, हमें ज्ञान आधारित संघर्ष में जरूर एकजुट हो जाना चाहिए, ताकि इन संघर्षों में बसे ज्ञान को समझा जाये और एक समान ज्ञान के आधार पर संघर्ष का निर्माण किया जा सके, ताकि खर्च में कटौती और—बड़े अधिवेशनों के आयोजन में, बयानों के प्रकाशन में, मानव ध्वनि-विस्तारकों के निर्माण में या स्वायत्त शिक्षा समूहों के निर्माण में—राज्य के दमन से निपटा जा सके, ताकि उन सभी ज्ञान के आधार पर नये समुदायों और समान संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जा सके। वह संघर्ष कैसा होगा जो आर्थिक और राजनैतिक दमन के विरोध के रूप में न खड़ा हुआ हो, बल्कि अंतर सामुदायिक, अंतर्राष्ट्रीय (यानि राष्ट्रों को विभाजित करने वाली सरहद को न पहचानने वाले) संघर्षों के, गैर मान्यता प्राप्त समान ज्ञान के बल पर खड़ा हुआ हो? क्या होगा, अगर भूमि के ज्ञान का उपयोग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने में किया जाये, प्रव्रजन में निहित ज्ञान का उपयोग सीमाओं को समाप्त कर देने के लिए किया जाये, विस्थापन के ज्ञान का उपयोग संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए किया जाये, निजीकरण और कटौती के ज्ञान का उपयोग संघर्षों से सीखने के लिए व सामान्य स्वायत्त स्थानों के निर्माण के लिए किया जाये? और क्या होगा अगर आत्म सशक्तिकरण के लिए पार-सामुदायिक औजार के रूप में इस ज्ञान को मान्यता प्राप्त ज्ञान से सम्बद्ध कर दिया जाये?

(मूल लेख अंग्रेजी में वियना से प्रकाशित एक इंटरनेट पत्रिका के लिए लिखा गया था, उसका हिन्दी अनुवाद रविशेखर ने किया। उस लेख का अंतिम भाग हमने यहां प्रकाशित किया है। ***–सम्पादक****)*

•

लोकविद्या जन आंदोलन को मजबूती से फैलायें

सेवाग्राम आश्रम में विद्या आश्रम न्यास की बैठक

सेवाग्राम में बापू कुटी की छाया में 17मार्च 2012 को विद्या आश्रम न्यास की वर्ष 2011-12 की बैठक हुई। इस बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से न्यास के सदस्यों ने शिरकत की और लोकविद्या विचार व लोकविद्या जन आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प जाहिर किया। विद्या आश्रम न्यास के अध्यक्ष सुनील सहसबुद्धे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विद्या आश्रम के अगले चरण के कार्यों को चिह्नित करने व उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। वर्ष 2011-12 विद्या आश्रम के लिये महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इस वर्ष लोकविद्या जन आंदोलन को आकार दिया गया व लोकविद्या विचार का फैलाव बिहार व मध्य प्रदेश में हुआ। लोकविद्या ताना-बाना का विचार भी इसी क्रम में पैदा हुआ।

सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी और कस्तूरबा

विद्या आश्रम के अगले चरण के सवाल पर सभी ने अपनी राय व्यक्त की। अपने समाज की समझ, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, नई राजनीति की जरूरतें, क्षेत्रीय समस्याओं के हल की आवश्यकता, लोकविद्याधर समाज की एकता और लोकविद्या की ज्ञान मीमांसा आदि सभी विषयों पर सघन चर्चा हुई व इनके आपसी सम्बन्धों की पहचान की गई। लोकविद्या ताना-बाना, स्थानीय बाजार, जाति, नई राजनीति की अंतर्राष्ट्रीय पहल, नई तालीम, लोकविद्या उत्पादन के प्रयोग, असहयोग, किसान-कारीगर संगठन, क्रमिक बदलाव के विचार, लोकविद्या के विचार से शोध आदि मुद्दों पर अपनी-अपनी राय, पहल व जिम्मेदारियों के स्वरूप को सदस्यों ने रखा।

शोध के सिलसिले में आये विचारों को एकजुट करने और कार्य का एक प्रस्ताव बनाने के लिये गिरीश (नागपुर), कृष्णराजुलु (हैदराबाद), सुरेन्द्रन (पुणे) और सुरेश (बंगलुरु) ने संयुक्त जिम्मेदारी ली।

रचनात्मक कार्यक्रमों के संदर्भ में लोकविद्या आश्रमों के निर्माण के विचार को बल मिला। लोकविद्या कार्य के अपने सघन क्षेत्रों जैसे वाराणसी, विन्ध्य प्रदेश, मालवा, विदर्भ, आन्ध्र प्रदेश और मिथिला में लोकविद्या आश्रम बनाने की ठोस पहल अपेक्षित है, यह विचार बना।

लोकविद्या जन आंदोलन को समय और स्थान के हिसाब से विकसित होने देने और उनकी विभिन्न जरुरतों को विद्या आश्रम की क्षमता के अनुसार पूरा करने के विचार को बल मिला। कार्यालय और प्रकाशन के कामों को सुचारु रूप से चलाया जाना होगा।

दरभंगा से आये विजय कुमार व उनके साथियों ने दरभंगा में प्रस्तावित 31 मार्च - 1अप्रैल 2012 के बिहार लोकविद्या जन आंदोलन के प्रांतीय समागम की तैयारी को रखा। इन्दौर से आये संजीव कीर्तने और उनके साथ आये साथियों ने इन्दौर शहर के आसपास हो रहे विस्थापन से पीड़ित किसान और गाँववासियों की स्थिति को सामने रखा और उनके बीच लोकविद्या विचार से पहल के बारे में बतलाया। बाजार मोड़ो अभियान की शुरुआत के कदमों की चर्चा की। सिंगरौली से अवधेश व लक्ष्मीचंद दूबे ने अगस्त 2012 में होने जा रहे विन्ध्य क्षेत्र के लोकविद्या जन आंदोलन सम्मेलन की तैयारियों से बैठक को अवगत कराया। इस सम्मेलन का मूल मुद्दा बिजली के वितरण का, विस्थापन और सबको पक्की आय का होना है इस बात पर सभी की सहमति रही। हैदराबाद से नारायण राव व उनके साथियों ने 'लोकविद्या प्रपंचम' के प्रकाशन के मार्फत हो रही पहल को सबके बीच रखा। वाराणसी से दिलीप कुमार एवं लक्ष्मण प्रसाद ने किसानों के बीच संगठन कार्य और लोकविद्या जन आंदोलन के मुद्दों से लोकविद्याधर समाज के बीच एकता के अभियान को सामने रखा। गया से आये रवीन्द्र पाठक और प्रमिला पाठक ने मगध जल जमात के कार्यों से सबको परिचित कराया। वर्धा के विजय जावंधियाजी ने सूखी खेती के किसान को कृषि का सबसे बड़ा ज्ञानी कहा और लोकविद्याधर समाज के सभी वयस्कों को पक्की आमदनी होनी चाहिए—इस अभियान को शीघ्र शुरू करने की बात कही। हैदराबाद के ललित कौल और अभिजित मित्रा ने लोकविद्या जन आंदोलन के लिए वैचारिक भूमि को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक शोध और इस शोध की अवधारणा, पद्धति, सार, मूल्य इत्यादि को लोकविद्यापरक बनाने पर जोर दिया। विद्या आश्रम की समन्वयक चित्रा सहस्रबुद्धे ने विद्या आश्रम की वर्षभर की गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए प्रकाशन की गतिविधि में अधिक लोगों के शामिल होने की आवश्यकता को रखा।

•

लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन

गन्ने के बकाया मूल्य के भुगतान की मांग

लक्ष्मण प्रसाद

लखनऊ, 4 अप्रैल। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दिनांक 4 अप्रैल को गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ पर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों की बड़ी संख्या में भागीदारी हुई। उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीवान चंद चौधरी, प्रदेश महासचिव श्री घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराम लम्बरदार, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता चन्द्रपाल

फौजी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। यह प्रदर्शन मुख्यतया गन्ने के अन्तर बकाया मूल्य के भुगतान को लेकर आयोजित किया गया था।

सुबह 10 बजे गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ पर भारी संख्या में किसान एकजुट होकर नारा लगाना शुरू किये। शीघ्र ही प्रदर्शनकारी उसी स्थल पर पंचायत शुरू कर लाउडस्पीकर के मार्फत अपनी बात गन्ना आयुक्त तथा प्रशासन को पहुंचाने लगे। वक्ताओं ने चेतावनी दिया कि किसानों की गन्ना की समस्याओं का तुरन्त हल निकाला जाय अन्यथा कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। वक्ताओं ने कहा कि सत्र 2006-07 में रुपये 7/- प्रति कुंतल तथा सत्र 2007-08 में रुपये 15/- प्रति कुंतल अन्तर बकाया मूल्य का भुगतान आज तक नहीं किया गया। इसी मुद्दे को लेकर 2 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर प्रदर्शन किया गया था। उस समय गन्ना आयुक्त महोदय ने कहा था कि चूंकि अन्तर बकाया भुगतान का मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए फिलहाल भुगतान नहीं किया जा सकता। कोर्ट जो आदेश देगा हम वैसा करेंगे। विगत 16 जनवरी को कोर्ट ने अन्तर बकाया भुगतान करने का आदेश दिया परन्तु आज तक भुगतान का कार्य रुका हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि गन्ना आयुक्त महोदय को अपने किये गये वायदों को पूरा करना चाहिए था। आज किसान निर्णायक संघर्ष के लिए कमर कस कर पूरी तैयारी से आये हुए हैं। लड़ाई आर-पार की होगी। इस पार की होगी या उस पार की होगी।

वक्ताओं ने कहा कि मुट्ठीभर सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया छठा वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गयी और देश के 80% किसानों के हित में बनाये गये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में बहस भी नहीं हो रही है। यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाय तो किसानों के 80-90 प्रतिशत समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा। दाम, भूमि-अधिग्रहण, बिजली, सिंचाई इत्यादि अनेक सवाल समाप्त हो जायेंगे और देश का किसान खुशहाल होगा। दिन में लगभग साढ़े ग्यारह बजे गन्ना आयुक्त कामरान रिजवी ने वार्ता करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष दीवान चंद चौधरी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गन्ना आयुक्त से वार्ता करने गया। गन्ना से संबंधित कई मुद्दों तथा गन्ना से भिन्न अन्य मुद्दों पर यह प्रतिनिधि मंडल अपनी बात रखा। गन्ना आयुक्त महोदय ने सचिव स्तर पर शासन से वार्ता कराने को कहा और शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया।

शाम 4 बजे गन्ना आयुक्त के साथ यह प्रतिनिधि मंडल सचिव स्तर पर वार्ता करने पहुंचा। प्रमुख सचिव कृषि एवं ऊर्जा श्री राजीव कपूर से लम्बी वार्ता हुई। इस वार्ता में सचिव महोदय ने आश्वासन दिया कि 17 अप्रैल के बाद अन्तर बकाया मूल्य का भुगतान कर दिया जायेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वर्तमान सत्र में भी सख्ती बरती जायेगी और किसानों के गन्ना का भुगतान कराया जायेगा। घटतौली के संबंध में उन्होंने कहा कि गन्ना क्रय केन्द्रों पर आकस्मिक रूप से कांटे की जांच की जायेगी। खाता नंबर अथवा नाम में गलती हो जाने के कारण किसानों की भुगतान की गयी गन्ने की पेंडिंग पड़ी धनराशि गन्ना विकास समिति को हस्तांतरित कर दी जायेगी जहां से किसानों को उनकी धनराशि मिल जायेगी।

... शेष पृष्ठ 8 पर

ऐढ़े गांव में लोकविद्या युवा शिविर

लक्ष्मण प्रसाद

भारतीय किसान यूनियन वाराणसी द्वारा विकास खंड हरहुआ अंतर्गत ऐढ़े गांव में 24 मार्च 2012 को किसान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में निम्नलिखित बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया :

असली ज्ञानी कौन? :

समाज में हम देखते हैं कि एक तरफ किसान अपने खेतों में अनाज, फल, सब्जी इत्यादि पैदा करता है, कारीगर कपड़ा, घर-मकान तथा जरूरत की बहुत सारी चीजें बनाता है। छोटे-छोटे दुकानदार और पटरी के व्यवसायी छोटी पूंजी में धंधा करके अपने परिवार को संचालित करते हैं, सामान्य स्त्रियां खाने-पीने के सामान तथा वस्त्र निर्माण कला में निपुण होती हैं, आदिवासी समाज अपने ज्ञान व श्रम से जंगलों के उत्पादों/औषधियों इत्यादि को संकलित कर समाज की जरूरतों को पूरा करने में लगा है। दूसरी तरफ स्कूल-कॉलेज से पढ़-लिखकर निकलने वाला वर्ग पद व प्रतिष्ठा पाकर लोकविद्याधर समाज को लूटने में लगा है। हमारे सामने सवाल यह है कि स्कूल-कॉलेज-यूनिवर्सिटी की विद्या से प्रायः दूर लोकविद्याधर समाज को हम ज्ञानी कहें अथवा स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ कर समाज को लूटने वाले लोगों को हम ज्ञानी कहें। हमारा दावा है कि अपने खेत में एक किसान जिन संसाधनों के साथ उत्पादन कर देता है यदि उस स्थान पर कृषि विज्ञान के प्रोफेसर को खड़ा कर दिया जाय तो वह भाग खड़े होंगे। उनका किताबी ज्ञान सिर्फ क्लास रूम और प्रयोगशालाओं में कारगर साबित हो सकता है, खेत-खलिहानों में नहीं।

हर वयस्क को पक्की नौकरी :

अपने-अपने काम के क्षेत्र में सब जन ज्ञानी हैं। अतः योग्यता का मापन डिग्री/सर्टिफिकेट रखना सही नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है, उस काम का ज्ञान भी वही रखता है। इस सिद्धान्त के आधार पर योग्यता तय होनी चाहिए। वे ही परिवार खुशहाल हैं जिन परिवारों की पक्की आय होती है। उद्योगपति, व्यापारी, नेता, सरकारी नौकरी करने वाले लोग खुशहाल हैं। सरकार की नीति के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सबकी खुशहाली लाना सरकार का दायित्व है। अतः हर वयस्क को पक्की नौकरी मिले, ऐसी नीति बननी चाहिए और ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए। सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो काम आता है, उसी काम की पक्की नौकरी मिलनी चाहिए।

बिजली :

गांववासियों ने बिजली के संबंध में बात उठायी कि दलित बस्ती में गरीब परिवारों को शासन की ओर से मुफ्त बिजली देने की बात की जाती है। लेकिन इस ऐढ़े गांव में दलित बस्ती के लोग बिजली के अभाव में अंधेरे में रहते हैं। इस शिविर में लोगों ने मुफ्त बिजली के लिए संघर्ष करने का मन बनाया।

भूमि-बंटवारा :

गांव के लोगों ने यह बात भी उठाई कि गांव सभा की जमीन पर अनाधिकृत लोग काबिज हैं। गांव सभा की जमीन गांव के भूमिहीन लोगों के बीच बांटी जाय। इसके लिए हर सम्भव संघर्ष किया जायेगा।

भागीदारी :

इस शिविर में भारतीय किसान यूनियन, वाराणसी मण्डल के महासचिव श्री दिलीप कुमार दिली, वाराणसी जिलाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, कृष्ण कुमार क्रांति, बबलू कुमार, बुद्धिराम उपस्थित थे। गांववासियों में मनोज कुमार, जितेन्द्र कुमार, मुसाफिर, निहोरी लाल, परमात्मा, अलगू राम, राजेन्द्र, बेचन लाल, फूलचंद, राजकुमार, मंजीत कुमार, पिन्टू कुमार, सुजीत कुमार शामिल रहे। ये लोग कारीगरी के विभिन्न कार्यों द्वारा अपनी जीविका संचालित करते हैं। युवाओं में संगठन के प्रति उत्साह था और उन्होंने भारतीय किसान यूनियन को मजबूत करने की वचनबद्धता दोहराई।

●

बुन्देलखण्ड के किसानों की मांगें

1. संपूर्ण किसानों के छोटे-बड़े कर्जे माफ किये जायें,
2. कृषि संबंधित सभी प्रकार राजस्व वसूली बंद की जाये,
3. निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन फ्री किये जायें,
4. नरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाये,
5. बुंदेलखण्ड में बिजली की एक समानता करके बिल वूसली पूरे प्रदेश में की जाये इस समय बुंदेलखण्ड में 130/- प्रति हॉर्स पॉवर लगता है, जबकि बुंदेलखण्ड को छोड़कर पूरे प्रदेश में 75/- प्रति हार्सपॉवर बिल लगता है,
6. यह कि बुंदेलखण्ड के असिंचित क्षेत्रों में पैदा होने वाली फसल चटरी पर उत्पादन व बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाये। बिक्री की छूट दी जाये,
7. बुंदेलखण्ड में अन्ना व आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान होने से बचाया जाये,
8. यह कि बुंदेलखण्ड में वृक्षारोपण किसानों के माध्यम से किया जाये एवं वृक्षों की सुरक्षा हेतु तार फेसिंग फ्री कराई जाये,
9. यह कि बुंदेलखण्ड की जंगलों की बेरीकेटिंग तार फेंसिंग कराकर जंगली जानवारों से रोका जाये,
10. वन कटान को रोका जाये एवं वन कटान पर आश्रित परिवारों को चिन्हित कराकर रोजगार में जोड़ा जाये,
11. बुंदेलखण्ड में बालू एवं अवैध खनन व पत्थर सहित तत्काल रोका जाये,
12. बुंदेलखण्ड में किसानों के आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे वापस लिये जायें,
13. यह कि चित्रकूट धाम मण्डल में पिछली पंचवर्षीय में मनरेगा में की गयी धनराशि की जांच कराई जाये,
14. भूमि संरक्षण विभागों द्वारा बंधी चैक ड्रिम निर्माणों की जांच कराई जाये।
15. बुंदेलखण्ड में कृषि विकास योजनाओं की निगरानी हेतु निगरानी समितियां बनायी जायें तथा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्यों को समितियों में शामिल किया जाये।

निरंजन सिंह राजपूत
जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, हमीरपुर

बुंदेलखण्ड के किसानों का ज्ञापन

सेवा में, दिनांक 5-3-2012
महामहिम राज्यपाल महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

श्रीमान,

विषय : बुन्देलखण्ड (हमीरपुर) सहित सभी जिलों में जैसे बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन आदि जिलों में किसान संबंधित समस्याएं।

1. विद्युत संबंधी समस्याओं से सभी जिले हमीरपुर सहित जूझ रहे हैं। पूर्ण क्षमता से बिजली न मिलने के कारण, दो-दो, तीन-तीन दिन बिजली न मिलने से और आये दिन जर्जर तार टूटने से 24 घंटे में सिर्फ 8 या 10 घंटे विद्युत मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं तथा विद्युत के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है और विद्युत बिल का अन्तर पूरे उत्तर प्रदेश से हटकर बुंदेलखंड से 130 रुपये प्रति हार्सपॉवर अधिक पूरे साल का बिल लिया जाता है जबकि पूरे प्रदेश में 75 रुपये प्रति हार्सपॉवर की दर से बिल का भुगतान किया जाता है।
2. इस समय अधिक वर्षा के कारण फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान है—मटर, मसूर का 100% नुकसान, अरहर में 50% का नुकसान, चना, गेहूं, चटरी का 50% नुकसान किसानों को हुआ है जिससे किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गये, इससे पहले भी कई वर्षों से सूखा, बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि से फसलों का प्रतिवर्ष किसानों को नुकसान हुआ इस कारण किसान भुखमरी व आत्महत्या के लिए मजबूर हैं और बुंदेलखण्ड में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यदि बगैर पानी वाली फसल जैसे चटरी किसान बोते हैं तो किसानों को चटरी बेचने पर रोक लगाकर मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया जाता है जो वर्तमान में किसानों पर मुकदमे चल रहे हैं इन्हीं समस्याओं को देखते हुए किसानों के सभी कर्जे माफ किये जाएं।
3. बुंदेलखण्ड के सभी जिलों में बालू, पत्थर का अवेध खनन वर्तमान में बहुत तेजी से हो रहा है जिससे कुंओं व ट्यूबेलों का जलस्तर तेजी से घट रहा है व माफिया व आला अधिकारी जोरों से फलफूल रहे हैं। यह सब नेता, पुलिस प्रशासन के कारण सभी अवैध व्यापार फलफूल रहे हैं।

निरंजन सिंह राजपूत
जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, हमीरपुर

संस्मरण

लोकजीवन में न्याय का प्रकाश

प्रेमलता सिंह

यह वाकया सन् 1956 की बाढ़ के समय का है। जब क्वार महीने में पूर्वांचल की कर्मनाशा, चन्द्रप्रभा और गड़ई नदियां करार तोड़कर उफन रही थीं। सात दिन से मुसलाधार बारिश हो रही थी। सूर्य का दर्शन दुर्लभ था। तब के वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील के कई गांव पानी में डूब गये थे। काशी नरेश के चकिया स्टेट (चकिया तहसील) के गांवों में भी पानी समाता जा रहा था। इसी तहसील के उतरौत गांव सभा के भभुआर मौजे का राजबाहा जिसका उदगम कर्मनाशा से था, अपनी बाढ़ विभीषिका में पड़वा, बछिया, बकरियां बहाये लिये जा रहा था। कहते हैं कि खटोलने पर सोये बच्चे कजरौटा सहित बह गये थे। राजबाहा के किनारे पर खेत-मजदूरों के आठ से दस घर थे। हरहराता हुआ पानी करार की मिट्टी को काट रहा था। उन लोगों के घर बैठने लग गये। यही नहीं भभुआर ताल का पानी ऐसा रेला मारा कि कच्ची सड़क पार कर उनके घरों में सामने की ओर से पहुंचने लगा तब यह ताल 5 बीघे का था। इधर गांव की गलियां लबालब तो थीं ही सो घरों के आंगन का पानी भी निकलना मुश्किल हो रहा था। परिणाम स्वरूप कुछ मकानों में भी पानी पहुंच गया।

मनसा देवी इसी उतरौत गांव की लगभग साठ-पैंसठ साल की वय, उदारमना, निर्भीक, सूझ-बूझ वाली महिला थीं। उनके अपने मजदूरों के घर भी भभुआर में थे। उनका हाल मालूम करने के लिए वे परेशान होने लगीं। जब कुछ नहीं सूझा तब अपने मकान के ऊपरी हिस्से के पूर्वी छोर से टिन के भोंपू से कई आवाजें लगायीं। वैसे उनका यह तरीका खुले मौसम में कारगर होता था लेकिन घनघोर बारिश में उनकी ध्वनि किसी ने सुनी या नहीं यह तो नहीं मालूम लेकिन शाम नहीं हुई और मजदूर अपने कुनबे के साथ मवेशी और बर्तन-भांडे लेकर मनसा देवी के दालान में आ धमके। अपने कोठे वाली बैठक के निचले हिस्से में जगह की व्यवस्था करने के बाद राशन, गोहरी, नमक का भी प्रबंध कीं। पन्द्रह दिनों के बाद बारिश थमी लेकिन बाढ़ उतरने और भूमि पर ठीक से आवाजाही शुरू होने में लगभग एक माह लग गया।

इस प्रलय की घड़ी में डुबान क्षेत्र के मजदूर अपने-अपने गृहस्थों के यहां डेरा डाले हुए थे। गृहस्थों के घर से ही उनका राशन-पानी चल रहा था। उन दिनों गांव में डेढ़िया लेने का चलन था यानि कि एक सेर अनाज देने के बदले जब अनाज उत्पन्न होता था तो डेढ़ सेर वसूल लेते थे। यदि वसूली नहीं हो पाती थी तो उस वर्ष कर्ज चढ़ जाता था। मनसा देवी इस चलन को नहीं मानती थीं, जितना देती थीं उतना ही लेती थीं। यह सभी को मालूम था। परन्तु बाढ़ के समय मजदूरों को खिलाये गये राशन में से पन्द्रह दिनों के राशन का हिसाब छोड़ दिया। यह बात गांव में बड़ी तेजी से फैल गयी। सभी गृहस्थ परेशान होने लगे कि मजदूर मनबढ़ हो जायेंगे। मस्टराइन भौजी यह नया रिवाज क्यों लगाने लगीं। सच्चाई जानने के लिए कुछ गृहस्थ लोग उनसे मिलना चाहे। मनसा देवी एक छोटी पंचायत बुलाईं। छोटे-बड़े कई गृहस्थ आये। उन्होंने समझाते हुए बताया कि इन मजदूरों की बदौलत ही हमारी खेती होती है, अन्न से कुठले-कुंडे भरते हें, और हम सब लोग शान से जीवन बिताते हैं। एक सेर खानगी के बदले डेढ़ सेर लेते भी हैं। लेकिन इस प्रलय में जब हमारी ही फसल ठीक नहीं होगी तो मजदूर कहां से चुकायेंगे और खायेंगे क्या? खायेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे करेंगे?

मजदूरी के खेतों और बटाई के खेतों की फसल इस लायक नहीं बची कि ये लोग कर्ज चुका सकें। वे लोग भी मानुष हैं, हमारे ही आदमी हैं, हम पर आश्रित हैं और हमारी खेती इन लोगों के आसरे ही होती है। यदि हम उनको पन्द्रह दिनों का राशन बिना मूल्य के खिला देंगे तो हम गृहस्थों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात डेढ़िया वाली के लिए आप सब लोग खुद ही सोचें। हमें यह चलन अन्यायी लगता है इसलिए हम अपने तईं इसे बन्द कर दिये हैं। क्योंकि धान की रोपाई-निराई के बाद मजदूरों के लिए हमारे पार कोई ठोस काम नहीं रहता है। डेढ़ महीने तक वे लोग हमसे अनाज लेकर पेट-तन चलाते हैं। पुनः धान की फसल तैयार होने पर उनकी कमाई डेढ़िया पाटने में निकल जाती है। यदि नहीं पूरा हो पाता तो रबी की फसल से भी चुकता करते हैं। आप लोग सोचें कि एक ओर हम कहते हैं कि ये हमारी प्रजा हैं दूसरी ओर उनको भूखे मारने की रीति चलाते हैं। यह कहां का न्याय है? वे भी उसी भगवान की औलाद हैं जिसने धरती पर अन्न, जल, पेड़, जीव-जन्तु बनाये। अपना और अपने कुनबे का पेट भरने का उनका भी हक है। हम उन्हें जितना अनाज देंगे उतना ही अगली फसल से लेंगे। यह हमारा अपनी ओर से पक्का फैसला है।

•

करसड़ा में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत

बबलू कुमार

वाराणसी में कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड के विरोध में करसड़ा, चुरामनपुर, बेटावर, गोसाईंपुर के किसानों ने विगत 29 जून, 2011 से अपने धरने को अनवरत जारी रखा है। इसके बीच तीन बड़ी-बड़ी पंचायतें लगाकर शासन-प्रशासन से संघर्ष भी किया। फरवरी 2012 से ए टू जेड कंपनी कूड़ा भी गिरा रही है। कूड़ा सड़ने से करसड़ा और

आसपास के गांवों में काफी दुर्गन्ध फैल रही है और वहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इस गंदगी से गांव में रहना और जिंदगी बिताना कठिन हो चुका है। इससे आजिज होकर गांव के लोगों ने 25 मार्च 2012 को एक बड़ी पंचायत लगाने के लिए गांव-गांव में जुलूस निकालकर लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार-प्रसार किया कि यदि 25 मार्च को कूड़े की कोई भी गाड़ी आती है तो हम लोग उसे रोक देंगे। इसके डर से उस दिन कूड़े की गाड़ी नहीं आयी। पंचायत 11 बजे शुरू की गयी। पंचायत में गांव-गांव से भारी संख्या में महिला-पुरुषों ने भाग लिया। गांव की सभी महिलाओं की ओर से एक ही बात सामने आ रही थी कि 'मारेंगे या मरेंगे' लेकिन कूड़ा डम्पिंग हटायेंगे। यहां नौजवानों ने भी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में एकजुट होकर अपने रोष को पंचायत के सामने रखा और कुछ क्षण के लिए सड़क पर आकर जाम लगाने का भी प्रयास किया। चूंकि यह पंचायत का निर्णय नहीं था इसलिए जाम तुरन्त समाप्त करना पड़ा।

पृष्ठ 7 का शेष

लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन

गन्ना के अलावा किसानों की अन्य मांगों पर भी प्रमुख सचिव कृषि एवं ऊर्जा श्री राजीव कपूर ने कहा कि आप की समस्याओं एवं मांगों को विचारार्थ रखा जायेगा। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार गेहूं के लागत मूल्य पर 50% बोनस जोड़कर गेहूं का क्रय मूल्य निर्धारित करने की बात की गयी थी। चूंकि गेहूं का लागत मूल्य 12 रुपये आ रहा है इस पर 50% जोड़ने पर क्रयमूल्य 18 रुपये आ जाता है। अतः प्रदेश सरकार गेहूं का क्रय मूल्य रुपये 18/- प्रति किलो निर्धारित करे। इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात प्रमुख सचिव महोदय ने की। हर महीने की 22 तारीख को जिलाधिकारी के साथ किसानों के बैठक को जारी रखने की बात प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गयी। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि किसानों की तरह-तरह की समस्याएं आती रहती हैं, जिला स्तर पर मीटिंग में तमाम समस्याओं का समाधान हो जाया करता है जिससे किसानों को लखनऊ का चक्कर नहीं काटना पड़ता। इस पर प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि मैं अपनी तरफ से इस बात को आगे बढ़ाता हूं और आशा करता हूं कि महीने की 22 तारीख की मीटिंग पुनः शुरू की जायेगी। बिजली बिलों की पेनाल्टी माफ कर मूल धनराशि जमा करने की व्यवस्था शुरू करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस सवाल पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया जायेगा। प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि चूंकि प्रदेश की सरकार बदली है, व्यवस्थाएं बदली हैं अतः कुछ समय में उपर्युक्त सभी मुद्दों का समाधान कर दिया जायेगा।

प्रतिनिधि मंडल के अनुसार वार्ता काफी गंभीर और आशापरक रही। सम्भव है कि वार्ता के मुताबिक किसानों की मांगों को पूरा कर दिया जाये। परन्तु हमारी मांगों पर ठीक ढंग से कार्यवाई नहीं की गयी तो अगली रणनीति अगले महीने की पांच तारीख को प्रदेश की मासिक पंचायत में बनायी जायेगी। बड़ा आंदोलन छेड़ा जायेगा।

•

पंचायत में कुल 400 लोगों की भागीदारी रही। अंत में पंचायत में निर्णय लिया गया कि पूरे प्रकरण को कोर्ट के समक्ष लाया जायेगा और स्टे लेने की तैयारी की गयी। पंचायत में सलाऊ खान, बसन्त लाल, रामजी, हरिशंकर, मन्नू, चम्पा, चमेला, लालती, बबलू, कृष्ण कुमार, लक्ष्मण प्रसाद, दिलीप, भृगुनाथ, संतलाल इत्यादि लोगों ने विचार व्यक्त किये। पंचायत की अध्यक्षता श्री रामजीत यादव और संचालन श्री अशोकसत्ये जी ने किया।

•

तुमड़ी का शब्द

बद्री नारायण

यह सबद की तुमड़ी है
कि तुमड़ी का शब्द
कहना कठिन है
यह शब्द कितना शाश्वत है
कितना क्षणभंगुर
कहना कठिन है
यह कितना नानक का है
कितना कबीर का
कि कितना बोधा, रैदास का
हिगराना कठिन है
बिलगाना कठिन है
कि यह कितना है जौनपुर से आये खिलाड़ी राम का
इस शब्द में क्या है
बूझना कठिन है
इसमें कितने चाहते हैं, कितनी हसरतें
कितनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, स्वप्न घुले मिले हैं,
इसमें कितना भूत है कितना भविष्य
कहना कठिन है
कहना नहीं है आसान कि
इसमें कितना शामिल है इसे कहने
गाने, सुनने वालों का वर्तमान
इसमें कितना निछुका शब्द है
कितना टेक, कितना कहनी, रहनी और कितना छंद है
कितना आऽऽ, साऽऽ, रेऽऽ का योगदान है इसमें
जिस तुमड़ी से निकला है शब्द
वह कितना जोगी का है
कितना जती का
कितना राजा का
कि कितना है जन का और कितना जनतंत्र का
कहना कठिन है
पर सुनो! इस शब्द से निर्बल को बल मिलता है
निर्धन को धन
अंधे को आंख मिलती है
और बहरे को कान
इसमें निराकार को
निराकार में भी साकार मिलता है
इससे अपमानितों को सम्मान मिलता है
मिलती है इसमें निचलों को उठान
इन्हीं शब्दों से गरीबों में जनमता है
ताज और तख्त हिलाने का स्वप्न
देखो कितने तोप, तीर, तलवार,
आरी, कटार, तने हैं इस शब्द पर
कई फूलों के बाण से
इसे मारकर खा जाने
में सिद्धहस्त
लगाये बैठे हैं घात
डरता हूं मैं
इस शब्द के लिए डरता हूं
बीच-बीच में ढांढ़स बंधाता है मुझे
तुमड़ी पर गा गाकर नाचता भगैत
डरो मत कवि!
यह शब्द मरते ही जी जाता है।

तद्भव, अंक 23, जनवरी 2011 से साभार

बुक पोस्ट

लोकविद्या पंचायत, मासिक समाचार पत्र, विद्या आश्रम (सा 10/82 ए, अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007) की ओर से **डा.चित्रा सहस्त्रबुद्धे** द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित।
website : vidyaashram.org **Blog :** lokavidyapanchayat.blogspot.com , lokavidyajanandolan.blogspot.com **e-mail :** vidyaashram@gmail.com **Phone :** +91-9838944822
प्रेस : **सत्तनाम प्रिण्टर्स**, एस-1/208 के-1, नई बस्ती, पाण्डेयपुर, सारनाथ रोड, वाराणसी-221002